



मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की @ नम्मा बेंगलूर

Postal Regd.No. HQ/SD/523/2023-25 | शनिवार, 05 अप्रैल, 2025 | हैदराबाद और नई दिल्ली से प्रकाशित | website : <https://www.shubhlabhdaily.com> | संपादक : गोपाल अग्रवाल | पृष्ठ : 14 | मूल्य-6 रु. | वर्ष-7 | अंक-93

बिम्स्टेक समूह शिखर से इतर बैठक में पीएम मोदी ने उठाई बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज

युनुस को सुनाई खरी खरी

बैंकाक/नई दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद युनुस से द्विपक्षीय मुलाकात कर ली लेकिन भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव बरकरार है। पिछले साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शोख हसीना के पद से हटने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। दोनों नेताओं ने बहु-क्षेत्रीय और तकनीकी सहयोग के लिए बिम्स्टेक समूह के नेताओं की शिखर बैठक से इतर यह मुलाकात की। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को



हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं, माहौल को खराब करने वाली बयानबाजी से बचें

दोहराया है। मिसरी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मुहम्मद युनुस के साथ चर्चा के दौरान बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की भारत की इच्छा को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी आग्रह किया कि माहौल को

खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने सीमा पर कानून का सख्त पालन करने और अवैध सीमा पार करने की घटनाओं की रोकथाम के लिए सीमा सुरक्षा को सख्त बनाने पर भी बल दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश

में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत की चिंताओं को भी रेखांकित किया। बता दें कि बांग्लादेश बिम्स्टेक समूह का आगामी अध्यक्ष है। पिछले साल अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण अपदस्थ प्रधानमंत्री शोख हसीना के बांग्लादेश छोड़ देने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में खटास आ गयी थी। यह खटास तब और बढ़ गयी थी जब पिछले सप्ताह चीन की यात्रा के दौरान युनुस ने बीजिंग से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने को कहा और विवादास्पद रूप से इस बात का उल्लेख किया था कि इस संबंध में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर जमीन से घिरा होना एक अवसर साबित हो सकता है। हम आपको याद दिला दें कि युनुस ने कहा था, भारत के सात पूर्वोत्तर राज्य चारों ओर से जमीन से घिरे क्षेत्र हैं।

►10पर

मणिपुर हिंसा में 260 लोग मारे गए, लेकिन बंगाल में चुनावी संघर्ष में ही 250 लोग मार दिए गए : शाह

सामान्य स्थिति होते ही मणिपुर में हटेगा राष्ट्रपति शासन

नई दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्य सभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव रखा। सदन ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। अमित शाह ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच नॉर्थईस्ट में 11,327 हिंसक घटनाएं हुईं, लेकिन मोदी सरकार के दस साल में ये घटनाएं 70 प्रतिशत घटकर 3,428 रह गई हैं। सुरक्षाबलों की मृत्यु में 70 प्रतिशत और नागरिकों की मृत्यु में 85 प्रतिशत की कमी हुई है। मोदी सरकार ने नॉर्थईस्ट में 20 शांति समझौते किए हैं और 10 हजार से अधिक युवाओं ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया है। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा में 260 लोग मारे गए हैं, लेकिन बंगाल में तो चुनावी हिंसा में ही ढाई सौ लोग मार दिए गए हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि मणिपुर सरकार के सामने कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था, क्योंकि विश्व के पास यह प्रस्ताव लाने के लिए पर्याप्त सदस्य ही नहीं हैं। उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और फिर राज्यपाल ने भाजपा के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जद (यू) के 1 और कांग्रेस के 5 विधानसभा सदस्यों से चर्चा की। जब अधिकतर सदस्यों ने कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तब कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की, जिसे राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकार किया। अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को लगाया गया, जबकि दिसंबर, 2024 से आज तक मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भ्रांति फैलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 13 फरवरी,



2025 से 7 साल पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर में उस वक्त विपक्ष की सरकार थी और तब

►10पर

राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित

नई दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

राज्यसभा की कार्यवाही की शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हुए कि बजट सत्र में सदन की उत्पादकता 90 प्रतिशत रही है। सत्र का समापन बंदे मातरम् की धुन के साथ हुआ।

इससे पहले उन्होंने सदन में शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को विदाई उल्लेख किया। सत्र के अंतिम दिन सदन में पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द होने को लेकर हंगामा भी हुआ और सदन की कार्यवाही सुबह दो बार स्थगित की गयी। राज्यसभा का यह सत्र 31 जनवरी को आरंभ हुआ था और चार अप्रैल को समाप्त हो गया। सदन में इस सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक 2025 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये।

बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में केपी शर्मा ओली से मुलाकात पर पीएम मोदी बोले

नेपाल भारत के लिए बेहद अहम



बैंकाक, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बैंकाक में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच अद्वितीय और घनिष्ठ संबंधों की समीक्षा की। पीएम मोदी और उनके नेपाली समकक्ष ने भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी, लोगों के बीच संपर्क और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। ►10पर

वक्फ विधेयक संसद से पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय की खोज में अहम क्षण : मोदी

नई दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक पारित होने की आज सराहना की और कहा कि यह सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, संसद के दोनों सदनों से वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ►10पर



वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस सांसद जावेद



बिल को असांविधानिक करार देने की अपील

नई दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। इसके साथ ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को पहली याचिका भी दायर हो गई है। बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने यह याचिका दाखिल की है। सांसद जावेद ने वक्फ कानून में हाल ही में किए गए बदलाव को चुनौती देते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने अपनी याचिका में इस विधेयक के माध्यम से किए गए संशोधनों को मुस्लिम समुदाय के मूल अधिकारों के खिलाफ बताया है। जावेद के अलावा हैदराबाद से चुन कर आने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस प्रस्तावित कानून को चुनौती दे रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुस मुस्लिमीन के सांसद ओवैसी ने लोकसभा में इस विधेयक पर लगभग 12 घंटे लंबी चर्चा के दौरान भी इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया था। ओवैसी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए इस विधेयक के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बिल की प्रति फाड़ने की बात कही थी।

संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। मुस्लिम समुदाय के कई संगठन और विपक्ष के नेता इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर, सरकार का दावा है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और उनके सही उपयोग के लिए है तथा इससे गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यसभा में

►10पर

बजट सत्र 2025 में संसद ने बनाया नया रिकॉर्ड वक्फ संशोधन विधेयक पर 17 घंटे से अधिक चली चर्चा : रिजीजू



नयी दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने संसद के आज समाप्त हुए बजट सत्र में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर दोनों सदनों में रिकॉर्ड समय तक हुई चर्चा को ऐतिहासिक बताया और इसमें बिना स्थगन या हंगामा किये भाग लेने के लिए सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को धन्यवाद दिया। श्री रिजीजू ने संसद भवन परिसर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक में लोकसभा में 14 घंटे से अधिक और राज्यसभा में लगभग 17 घंटे तक चर्चा हुई। लोकसभा में तीन अप्रैल को तड़के तीन बजे तक और राज्यसभा में आज सुबह चार बजे तक कार्यवाही चली और इसमें कोई बाधा या

स्थगन नहीं हुआ। इस प्रकार से एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। इससे पहले कभी किसी विधेयक पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह सभी सांसदों एवं राजनीतिक दलों को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा में सरकार को अपेक्षा के अनुरूप ही वोट मिले हैं। राज्यसभा में एक दल ने अपने सांसदों को व्हिप जारी नहीं किया था और अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की छूट दी थी, जिस पर उसके सांसदों ने सरकार के पक्ष का समर्थन किया। यदि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने व्हिप जारी नहीं किया होता तो सरकार को ज्यादा समर्थन मिलता। उन्होंने दावा किया कि कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने निजी तौर पर कहा है कि व्हिप का बंधन नहीं होता तो वे विधेयक का समर्थन करते। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह श्रीमती गांधी का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस के वक्तव्य में जबरदस्ती बुलडोज करके विधेयक पारित करने की बात गलत है। सबने देखा है कि दोनों सदनों ने लंबी बहस की और सब संशोधन प्रस्तावों एवं मतदान के जरिये इसे नियमानुसार पारित किया गया है। इसलिए बुलडोज शब्द का इस्तेमाल अनुचित है। ►10पर

खामोशी को कमजोरी ना समझे मोदी सरकार : उमर अब्दुल्ला

वक्फ बिल के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने बुलाई इमरजेंसी बैठक ?



श्रीनगर, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुआई में उपमुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास फेयरव्यू गुफकार में एक आपातकालीन बैठक हुई। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायक और गठबंधन के सहयोगी शामिल हुए। बैठक के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने नई दिल्ली से आखिरी बार आग्रह किया कि वह जम्मू-कश्मीर में लोगों के व्यापक जनादेश को कमतर न आंके और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने दे।

मीडिया को जानकारी देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने कहा, आज की बैठक में संसद में पारित वक्फ बिल समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बिल देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और हम इसका विरोध करते हैं। दूसरा अहम मुद्दा जम्मू-कश्मीर की जनता द्वारा एनपी के नेतृत्व वाली सरकार को दिया गया जनादेश है। हमने एक बार फिर मांग की है कि भारत सरकार इस जनादेश का सम्मान करे, इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विधायकों ने आज सर्वसम्मति से ये दोनों प्रस्ताव पारित किए।

उन्होंने कहा कि केंद्र को हमारी चुप्पी और सहयोग को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा, हम आखिरी बार यह अपील अन-रोध के तौर पर नहीं बल्कि सख्त चेतावनी के तौर पर कर रहे हैं। हमें मजबूर न करें और उस जनादेश का सम्मान करें जिसकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं। ►10पर

अभिनेता मनोज कुमार का निधन



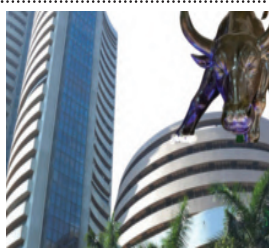
मुंबई, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

दिग्गज भारतीय फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। वह कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती थे एवं उन्हें लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी।

श्री मनोज कुमार के बेटे कुनाल गोस्वामी ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। फिल्म निर्देशक मनोज कुमार को देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता था। उनके निधन पर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों ने शोक व्यक्त किया है।

श्री मनोज कुमार को फिल्म उद्योग में उनके योगदान पर 1992 में पद्म श्री एवं 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

शेयर मार्केट



मौसम बेंगलूर

अधिकतम : 31°
न्यूनतम : 23°

महज पांच महीने की जम्मू कश्मीर सरकार

सीएम और एलजी में शुरू हो गई तकरार

सुरेश एस डुग्गर
जम्मू, 04 अप्रैल।

महज पांच महीने में ही जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच तकरार शुरू हो गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कुछ प्रशासनिक निर्णयों के खिलाफ कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा।

इस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वे अपने अधिकारों से पूरी तरह से वाकिफ हैं और वे अपनी लिमिट कभी

क्रॉस नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ गठबंधन के 46 विधायकों द्वारा हाल ही में उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा 48 जेकेएस अधिकारियों के तबादले के राजनीतिक और प्रशासनिक निहितार्थों पर निराशा व्यक्त करने के तुरंत बाद, एलजी सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि सभी कार्यवाही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में निर्धारित संवैधानिक ढांचे के भीतर सख्ती से की गई है। उपराज्यपाल ने कहा, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संसद ने



2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया और मैंने पूरी तरह से उस अधिनियम द्वारा परिभाषित सीमा के भीतर काम किया है। मैंने कभी भी अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है। मैं अपने अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकिफ हूँ। मैंने कभी उनका उल्लंघन नहीं किया है, न ही मैं ऐसा कभी करूंगा। इससे पहले मुख्यमंत्री उमर

अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर गठबंधन ने एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दो प्रमुख प्रस्ताव पारित किए, जिसमें वक्फ (संशोधन) विधेयक और उपराज्यपाल द्वारा हाल ही में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों का विरोध किया गया। नेकां विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि गठबंधन वक्फ (संशोधन) विधेयक की कड़ी निंदा करता है और इसे अल्पसंख्यक विरोधी और मुस्लिम विरोधी करार देता है। उन्होंने वक्फ सम्पत्तियों और जम्मू-कश्मीर में बड़े मुस्लिम

समुदाय पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने संकल्प लिया है कि लोगों के जनादेश का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जम्मू कश्मीर के एलजी और केंद्र सरकार के साथ समन्वय को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, उन्होंने कहा कि वे एकतरफा फैसलों के खिलाफ अंतिम अपील कर रहे हैं, खासकर एलजी मनोज सिन्हा द्वारा हाल ही में किए गए प्रशासनिक तबादलों के मद्देनजर। ►10पर

कार्टून कॉर्नर



कंकाल मल्लिगे का था और सुरेश

अदालत ने बलात्कार के आरोप हटाने की प्रज्वल रेवन्ना की याचिका खारिज की

9 अप्रैल से शुरू होगी सुनवाई

वेगलू/शुभ लाभ व्यूरो।
प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, विधायकों और सांसदों के लिए विशेष अदालत ने गुजरात को पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ बलात्कार के आरोपों को खारिज करने की मांग की गई थी। अदालत ने अगली सुनवाई 9 अप्रैल के लिए निर्धारित की है। पूर्व प्रधानमंत्री एच दी देवगौड़ा के पोते रेवन्ना ने पिछले महीने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया गया था कि के आर नगर की एक महिला



द्वारा दर्ज बलात्कार के मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। हालांकि, अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया, जिससे मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। फैसले से



संट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उनके दादा एच डी देवेगौड़ा और चाचा, केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी द्वारा सार्वजनिक अपील के बाद, जर्मनी से लौटनेवाले पर 30 मई, 2024 की सुनहल बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उसे कानूनी कार्यवाही का सामना करने का अग्रह किया गया था। रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला अश्लील वीडियो की एक श्रृंखला की व्यापक जांच का हिस्सा है। मामले की संभालने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भारतीय दंड संहिता की एक धाराओं के तहत गंभीर अपराधों का विवरण देते हुए 2,144 पन्नों का आरोप पत्र दाखल किया है, जिसमें यौन

उप्टीड़न, बलात्कार और आपराधिक धमकी के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान शामिल हैं। इस मामले के अलावा, रेवत्रा और अन्य यौन उप्टीड़न मामलों में आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन सभी में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस बीच, उनके पिता और जेडी(एस) विधायक पिता जी रेवत्रा को भी संबंधित मामले में जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वर्तमान में वे रेवत्रा की मां भवानी रेवत्रा के साथ जमानत पर बाहर हैं। उनके भाई, जेडीएस एमलुसी सूरज रेवत्रा, जिन पर पार्टी के पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ यौन उप्टीड़न का आरोप है, भी जमानत पर बाहर हैं।

बेंगलूर/शुभ लाभ व्यूरो।
कोरमंगला पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक सेवानिवृत्त सहायक कार्यकारी अभियंता को फोन कर हनीट्रैप वीडियो के जरिए धमकी दी थी और 2 करोड़ रुपये की मांग की थी।



दि कि अगर दो करोड़ रुपये नहीं दिए तो वे यह वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर देंगे। जब सेवानिवृत्त इंजीनियर ने इस बात से चिंतित होकर वीडियो देखने को कहा, तो उन्होंने उन्हें कोरमंगला में एक कॉफी बार में आने को कहा। जब वह कॉफी बार में गए, तो आरोपियों ने उन्हें कुछ वीडियो दिखाया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह उनका नहीं है, फिर भी वे पैसे की मांग करते

रहे और उन्हें धमकाते रहे। शुरुआत में 25 लाख रुपये की मांग की गई। इन युवकों के व्यवहार से निराश होकर उन्होंने कोमंगला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाकर उममें से दो को गिरफ्तार कर लिया तथा फरार आरोपी की तलाश कर रही है।

डीजल और टोल शुल्क में बढ़ोतरी से उडुपी में बस किराया वृद्धि पर चिंता

उडुपी/शुभ लाभ व्यूरो।
 डीजल की कीमतों और टोल शुल्क में हाल ही में हुई बढ़ोतरी का कड़ा विरोध हो रहा है। यह बढ़ोतरी दूध और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए दरों में वृद्धि के बाद की गई है। इस वृद्धि से रोजमर्रा की वस्तुओं पर असर पड़ने की उम्मीद है और इससे निजी बस किराए में भी वृद्धि सनकती है। डीजल और टोल शुल्क दोनों में वृद्धि के साथ, बसों, माल वाहक और अन्य डीजल चालित वाहनों के मालिकों पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ गया है। मैंगलूरु-उडुपी-कुंडापुर-भटकल मार्ग, जिस पर निजी बसों का भारी आवगमन होता है, विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। राज्य निजी बस मालिक संघ के अध्यक्ष सुरेश नायक ने कहा कि किराए में संशोधन अपरिहार्य होता जा रहा है। कुछ महीने पहले ही डीजल की कीमतों में ३ रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी और अब इसमें



2 रुपये की और बढ़ोतरी हुई है। टोल शुल्क में बढ़ोतरी से हमारा मासिक खर्च और बढ़ गया है, जो प्रति वाहन 25,000 रुपये तक बढ़ सकता है। सरकार से अपील के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हम जल्द ही बस मालिकों की बैठक करेंगे और आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे। इसका असर पिछले बसों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ट्रक, टेम्पो और टैक्सियों जैसे डीजल से चलने वाले वाहनों को भी परिचालन लागत में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। उडुपी टैक्सीमेन एसोसिएशन के महासचिव रमेश कोटयान ने इस

बात पर जोर दिया कि कीमतों में इस बढ़ोतरी से जीवन यापन की लागत प्रभावित होगी और उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यदि सुधारवात्मक उपाय नहीं किए गए तो परिवहन संघ भविष्य के विरोध पर निर्णय लेने के लिए जल्द ही बैठक करेंगे। इस बीच, सीआईटीए के उडुपी जोन समन्वयक कविराज एक कंचन ने कहा कि संघ राज्य और केंद्र सरकार की मूल्य निर्धारण नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज करने की तैयारी कर रहा है, जो आम लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं।

कांग्रेस विधायकों के करीबी
द्वारा विनय को लगातार किया
गया परेशान: आर. अशोक

बेंगलूर/शुभ लाभ व्यूरो विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि आत्महत्या करने वाले मडिकेरी के भाजपा कार्यकर्ता विनय सोमैया को वहां की सपा के समर्थन से कांग्रेस विधायकों के करीबी सहायगी द्वारा लगातार प्रेशन किया जा रहा था। आशोक ने आरोप लगाया है कि इस मौत के लिए ये तीनों लोग और एसपी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। कार्यकर्ता ने विधायक से धमकी मिलने का आरोप लगाया है। विनय को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा पुलिस तो उनके बेंगलूर स्थित घर तक भी आई थी। उन्होंने कहा उन्होंने पुलिस स्टेशन को कांग्रेस कार्यालयों में बदल दिया है। उन्होंने पुलिस पर दबाव डाला। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा इसका इस्तेमाल राजनीतिक नफरत का बदला लेने के लिए किया जा रहा है। हम पार्टी नेताओं के साथ मिलकर आली लड़ाई पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। हम किसी भी कारण से उनके परिवार के साथ हैं। हम उन्हें न्याय देंगे। उन्होंने कहा शिकायत में मैना, पोन्नरा और मंथर गौड़ा के नाम का उद्धेख किया गया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा हम कोडागु में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं।



बेंगलूर/शुभ लाभ व्यूरो। पससी महाविद्यालय राजाजीनगर में अंतर महाविद्यालय उत्सव संभव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 25 से भी ज्यादा महाविद्यालयों के 400 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। 20 से भी ज्यादा स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। विशिष्ट अतिथि महेंद्र मुण्ठाते ने अपने वक्तव्य में कहा राष्ट्र सेवा के लिए जरूरी नहीं की कोई नेता या अधिकारी बने, सामान्य नागरिक भी अपने कर्तव्यों का सही पालन करें तो वह राष्ट्र सेवा है। महाविद्यालय के सहायक प्राचार्य विजय कुमार, नागेंद्र बीएल, गणपति भट्ट एवं विश्व आरधने ने मुण्ठाते को सम्मानित किया।

अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना

बंगलूर/शुभ लाभ व्यूरो।
 मानसून पूर्व बारिश में सुधार
 ना है और गुरुवार को राजधानी
 बंगलूर सहित राज्य के कई हिस्सों
 में बारिश हुई। कुछ स्थानों पर
 मध्यम बारिश हुई, जबकि अन्य
 स्थानों पर भारी बारिश हुई। हवा
 पर बारिश के कारण बंगलूर
 केत कुछ स्थानों पर पेड़ और
 जंगली के खेपे गिर गए, जिससे
 कुछ समय के लिए जनता को
 सुविधा का सामना करना पड़ा।
 दक्षिण कन्नड़, बेंगलूर,
 बंगलूर, बागलकोट, विजयपुरा,
 त्रजनगर, बल्लारी, कोपल,
 चन्नूर, कोलार और चिक्कबल्लारपुर
 में बारिश दर्ज की गई, कुछ
 स्थानों पर छिपुट और व्यापक
 बारिश गुरुवार सुबह और
 दोपहर में बेंगलूर में बारिश हुई।
 चिक्कवतपुर, महालक्ष्मी लेआउट,
 टीपीएम लेआउट, बसवनगुडी,



जयनगर, नयंदहल्ली, राजाजीनगर, बोम्मनहल्ली, गांधीनगर और शिवाजीनगर समेत कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य में शाम और रात में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा गरज के साथ छींटे



पड़ेंगे। बिजली चमकने के साथ बारिश होगी। संकेत हैं कि बारिश तीन दिनों तक जारी रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है।



बंगाल की खाड़ी से, अर्थात् राज्य के दक्षिण-पूर्व से, ठंडी, तेज हवाएँ चलती रहेंगी। इसके परिणामस्वरूप कुछ स्थानों पर मौसम ठंडा हो जाएगा। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अंदरूनी इलाकों में गहरा गर्त

बनने के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। केवल तटीय और अंतर्देशीय कुछ भागों में भारी वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिणी आंतरिक और उत्तरी आंतरिक भागों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। बेंगलूर के आसपास आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा शाम और रात के दौरान बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा चामराजनगर, मांड्या, रामानगर, बेंगलूर शहरी, बेंगलूर ग्रामीण, बिक्रमपुर, कोल्हापुर, तुमकुरु, हसन, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, शिवमोग्गा, हावेरी, दावणगरे, गदग, धारवाड़, बेलगावी, उत्त कन्नड़, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, चिजनगर, बल्लारी, कोपल, रायचूर, बीदर जिलों में मध्यम बारिश की उम्मीद है।

कांग्रेस विधायकों के करीबी
द्वारा विनय को लगातार किया
गया परेशान: आर. अशोक
बेंगलुरु/शुभ लाभ ब्यरो। विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि
हमें हनी ट्रैप से बचने के लिए सतर्क
रहना होगा: सतीश जारकीहोली



बैंगलूर/शुभ लाभ व्यूरो।
लोक निर्माण मंत्री सतीश जाकरकीहोली ने कहा है कि हमें रहनी ट्रैप से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। यदि कोई आपको हाय कहता है तो आपको भी हाय नहीं कहना चाहिए, बल्कि बस बाय कहना चाहिए और भाग जाना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि न केवल मित्रियों को बल्कि सभी को सावधान रहना चाहिए। यहां यह जानना कठिन है कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। उन्होंने कहा कि हमें बस सावधान रहना होगा। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस आलाकमान के पीसीसी अध्यक्ष के पद में बदलाव के लिए कौन सा फार्मूला अपना रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मेरा और ईश्वर खंडे का नाम लिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वरिष्ठ

कीमतें बढ़ा दी थीं। पिछले दस वर्षों में तेल की कीमतों ने कितनी बार बढ़ी है? यही सभी मुख्य बिंदु का मूल कारण है। भाजपा ने इस पर विरोध क्यों नहीं जताया? जनसंख्या बढ़ गई है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि विकास के लिए मुख्य वृद्धि अपरिहार्य है और केवल विरोध करने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से विरोध करना चाहिए। दिल्ली में कर्नाटक भवन के निर्माण से 70 अतिरिक्त कमरे उपलब्ध हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली आने वालों के लिए आवास की समस्या कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राजमांगी पर टोल शुल्क में वृद्धि से कर्नाटक को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इस बार जब वे दिल्ली गए तो मुलाकामान के नेताओं से उनकी आलाका नहीं हो सकी। विधान परिषद सीट के

लिए कई लोग इच्छुक थे तथा अन्य नियुक्तियों की प्रतीक्षा करते रहे थे। इसलिए मैं आलाकमान के नेताओं से मिले बिना ही लौट आया। मंत्री के.एन. राजन्ना ने भी आलाकमान से मुलाकात नहीं की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। पुलिस मंत्री राजन्ना के हनीट्रैप मामले की जांच कर रही है। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की रिपोर्ट सामने आती है। हनीट्रैप मामले का अंत किया जाएगा। हनीट्रैप फर्जी है।

अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुदान हेतु कई अनुरोध किए गए हैं। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। डी.के. शिवकुमार ने कहा कि वह अपने विभाग में हो रहे घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए अन्य मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे।

घना धुआं छाने से दो बरसों आमने-सामने टकराई



मंगलूर/रुथ लाभ ब्यूरो।
पहाड़ी इलाके में आग लगने के कारण सड़क पर घना धुआँ छाने से गुरुवार की दोपहर को मंगलूर विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास के पास दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई।
कोनाजे से मंगलूर जा रही एक निजी बस और इनेली की ओर जा रही बीआईटी कॉलेज की बस के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिससे दोनों ड्राइवरों और कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं। कोनाजे विश्वविद्यालय के पास पहाड़ी इलाके में आग लग गई, जिससे पेड़ और झाड़ियाँ जल

गाई, जिसके कारण आसपास का इलाका धुएँ से भर गया। सड़क पर लपटों और धुएँ के कारण वाहन चालकों को दृश्यता की समस्या हो गई। इस भीषण, पासा आ रही दो बसों के ड्राइवर एक-दूसरे को देख पाने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों बसों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस तलहटी दिनों से मेंगलूत विश्वविद्यालय परिसर के भीतर पहाड़ी इलाके में आग लगी हुआ है, जिससे सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। बाद में दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया।

रायचूर विधायक की लोकेशन ट्रैक करने के आरोपों की जानकारी लूंगा: परमेश्वर



रही है। मैं एसपी और आईजीपी से बात करूंगा। यदि ऐसी घटना घटी तो क्यों घटी? उन्होंने कहा।

कि वे इसका कारण पता लगाएंगे और यह भी पता लगाएंगे कि इसकी अनुमति किसने दी, तथ आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने दो-हराया कि वैकस् बिल राजनीतिक कारणों से बनाया गया था न कि लोगों के हित में। विधान परिषद के लिए मनोनीत सदस्यों का चयन मध्यमर्ती और

केपीसीसी अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है। मुझे नहीं मालूम कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एआईसीसी नेताओं से बात की या नहीं। यह गलत है कि निरामातृता बोर्ड के मामले में मेरी सिफारिश पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और मैं शांति में हूँ। परिवर्धन के सदस्यों के चयन में मुझे शामिल करने की कोशिश आवश्यकता नहीं है। कई मामलों में अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। जब मैं

अध्यक्ष था तो कठिन निर्णय लेते समय सुनते थे। आसान निर्णय लेते समय मैं ध्यान नहीं दे रहा था। चार लोगों को नामांकित किया जाना आवश्यक है। इसका चुनाव चुनाव या स्थानीय निकायों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। मुंजिमही आसान है, इसलिए अध्यक्ष चुंकि यहाँ और कंपनीसी अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे और अनमति लेंगे।

सांसद मनोज तिवारी उत्तर- पूर्व जिला में, सांसद योगेन्द्र चंदोलिया उत्तर- पश्चिम जिला में, सांसद कमलजीत सररावत नजफगढ़ जिला में, सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी दक्षिणी दिल्ली में, सांसद बासुरी स्वराज करोल बाग स्थित जिला कार्यालय में, सांसद प्रवीन खडेलवाल चांदनी चौक जिला कार्यालय में, प्रदेश महामंत्री विष्णु मिश्रल केशवपुरम जिला कार्यालय में, श्री दिनेश प्रताप सिंह उत्तरी दिल्ली जिला कार्यालय में, श्रीमति सारिका जैन महरोली जिला कार्यालय में और श्री नरेश वशिष्ठ बहाड़ी दिल्ली जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।

समग्र रूप से इस कार्निवाल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को करेंगे। जीडीएल के सामने 25 एकर की जमीन और 1410 करोड़ रुपए की लागत पर इंटीग्रेटेड स्टेड ऑफ आर्ट्स सेंटर, क्लब एंड फाइव स्टार होटल निर्माण कराने जा रहा है। शिलान्यास शनिवार को के हाथों होगा। इसकी क्षमता 100 व्यक्तियों की होगी। इसका निर्माण तीन साल में पूर्ण करने का लक्ष्य है। कन्वेंशन सेंटर में एलिट आर्ट्स, प्राथमिक पुस्तकालय और एंटरटेनमेंट एंजनीबिशन लॉन का भी उद्घाटन किया गया है।

शनिवार, 05 अप्रैल, 2025

बेंगलूरू

सम्पादकीय

7

संपादकीय

भारत पर ‘जैसे को तैसा टैरिफ’

जैसा कि पूर्व घोषित था, उसी के मुताबिक अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26 फ़ीसदी ‘जैसे को तैसा टैरिफ’ भारत पर थोपने की घोषणा की है। इसे ‘मुक्ति-दिवस’ कहा जा रहा है। इस जमात में जापान, वियतनाम, सिव्ज़रलैंड, कंबोडिया, दक्षिण अफ़्रीका, इंडोनेशिया, ब्राजील और सिंगापुर आदि देश भी शामिल हैं, लेकिन अमरीका ने भारत के संदर्भ में यह ‘दोस्ती का ढोल’ पीटने के बावजूद किया है। हालांकि भारत-अमरीका के बीच 43 लाख करोड़ रुपए का ‘व्यापार सौदा’ भी निर्णायक चरण में है। इस साल के अंत तक इस पर मुहर लगाई जा सकती है। क्या उस व्यापारिक विमर्श में टैरिफ का मुद्दा शामिल नहीं किया जा सकता था? एलन मस्क की टेस्ला कार, प्रीमियम बाइक हार्ले डेविडसन और अमरीकी बर्बन व्हिस्की आदि पर भारत पहले ही टैरिफ-कटौती की घोषणा कर चुका है। अमरीका अपना गेहूँ, सेब, बेबी कॉर्न, मक्का सहित कई अन्य अनाज भी भारत में खपाना चाहता है। क्या भारत अनाजों की पैदावार में सक्षम नहीं है? यदि हम सक्षम हैं, तो ‘जैसे को तैसा टैरिफ’ झेलने या उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लिहाजा सबसे बड़ा बाजार भी है। चीन भी भारत के साथ अपने कारोबारी समीकरणों, खासकर आयात, को विस्तार देने के पक्ष में है। यदि अमरीका के साथ, टैरिफ चर्चाएं करने के बाद, व्यापार प्रभावित होता है, तो यूरोप और एशिया में नई संभावनाएं तलाश की जा सकती हैं। भारत का ‘यूरोपीय संघ’ के साथ ‘मुक्त व्यापार समझौते’ भी आखिरी दौर में है। भारत के कुल व्यापार का करीब 14 फीसदी यूरोपीय संघ के साथ होता है, जबकि अमरीका के साथ करीब 18 फीसदी है। बहुत ज्यादा फासला नहीं है।

इसे बढ़ा कर भरपाई की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अमरीका के देश भी भारत के नए व्यापारिक साझेदार बनने को तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को मात देने का सबसे कारगर तरीका यह है कि बाकी देश आपस में मौजूदा टैरिफ के आधार पर ही वसूली करें। इससे अमरीका दुनिया के व्यापारिक दायरे में अलग-थलग पड़ सकता है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ‘जैसे को तैसा कर’ लगाकर अमरीका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के पक्षधर हैं, जबकि यह योजना पलटवार साबित हो सकती है। अमरीका में टैरिफ घोषणा के बाद से खलबली मची है। कई क्षेत्रों के व्यापारी और उद्योगपति सकते में हैं। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अमरीकी भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लिहाजा सबसे बड़ा बाजार भी है। चीन भी भारत के साथ अपने कारोबारी समीकरणों, खासकर आयात, को विस्तार देने के पक्ष में है।

उसके साथ-साथ बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। खुद राष्ट्रपति ऐसी आशंकाएं जता चुके हैं, लेकिन उनके सहकाचारों के अनुमान हैं कि ‘जैसे को तैसा टैरिफ’ से अमरीका के खजाने में 43 लाख करोड़ रुपए सालाना का राजस्व आएगा। अमरीका के करीब 200 व्यापारिक साझेदार हैं। उनमें देश, प्रदेश-इलाके, क्षेत्रीय संघ आदि शामिल हैं। टैरिफ वर्ग करीब 12,500 हैं। ‘जैसे को तैसा टैरिफ’ के बाद कई और नए टैरिफ सामने आएंगे। अमरीकी प्रशासन के लिए उन्हें संभालना मुश्किल होगा। भारत के लिए भी नई चुनौतियां आएंगी। बहरहाल चीन की प्रतिक्रिया भी गौरतलब है। चीनी विदेश मंत्री ने ट्रंप के टैरिफवाद को ‘ब्लैकमेलिंग’ करार दिया है। यह अमरीका को कितना फायदा या नुकसान देता है, यह सोचने के बजाय भारत को अपने अनुकूल निर्णय लेने चाहिए।

कुछ

अलग

मंच हमारा, माला तेरी...

जिस समय वे मेरे यहां आए, चिंता की लकरीं ललाट पर स्पष्ट रूप से दिख रही थीं। वे मेरे परमपिय थे। सो बोला-‘क्यों, क्या बात है? मेरे लायक कोई कार्य हो तो बताओ। इतने निश्चित होने की बात क्या है?’ वे और अधिक गमगीन हो गए। लगभग रुआंसे होकर बोले-‘शर्मा मुझे बचा लो। मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। मेरी इज्जत दांव पर लग गई है। तुम तो घर के आदमी हो, दूसरे से कह भी नहीं सकते।।’ मैंने कहा-‘गिरधर जी मामला क्या है? आपकी इज्जत के लिए मैं अपना इज्जत दांव पर लगा दूंगा, आखिर बात क्या है?’ गिरधर जी अपना मुंह मेरे कान के पास लाए और बोले-‘शर्मा अपनी संस्था का वार्षिक कार्यक्रम वर्ष बीतेने को आया, लेकिन हो नहीं पा रहा है। साफ बात है संस्था आर्थिक विषमता में जी रही है। इस वर्ष सम्मान समारोह नहीं हुआ तो सारी बात खाक में मिल जाएगी, दूसरा गुट बदनामी करने पर तुला है।’ मैंने कहा, ‘तो कहिए, मुझे करना क्या है?’ गिरधर जी बोले, ‘तुम ऐसा करो, इस वर्ष का सम्मान ले लो। मेरी और संस्था की नाक बच जाएगी।’ मैं उनकी बात पर हंस पड़ा और बोला, ‘इसमें गिरधर जी चिन्ता की क्या बात है? इस वर्ष का साहित्य शिरोमणि सम्मान में ले लूंगा। आप तो चिन्ता को त्यागो और सम्मान की तैयारी करो।’ गिरधर जी लगभग पसर से गए और मौन साध गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने फिर कहा-‘क्यों अब क्या बात है? मैं सम्मान ले लूंगा, मना थोड़े ही कर रहा हूं।’ शर्मा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। मैंने अभी कहा कि संस्था पूरी तरह दिवालिया

है। मंच तो दे आयती है, लेकिन माला और दुशाला का ईतजाम कैसे होगा, सम्मान लेने वाले तो बहुत से हैं। तुम्हारी खुशामद करने का मेरा मतलब यही है कि तुम मंच के अलावा सारा ईतजाम मध्य से करो। वरना संस्था की मान्यता खतरे में पड़ सकती है, सम्मान का सारा व्यय तुम्हें ही संभालना होगा।’ गिरधर जी की बात सुनकर मुझे सूप सूंघ गया, समझ में ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। हालांकि सम्मान की लार मेरे मुंह में आ चुकी थी। वैसे भी साहित्य का कोई पुरस्कार सम्मान मध्ये अभी तक नहीं मिल पाया था। मैंने कहा-‘मैं आपकी बात समझ गया गिरधर जी, लेकिन पैसे से तो मैं भी बहुत तंग हूँ, गए महीने पी. एफ. से लोन लेकर घर की व्यवस्था की थी। अब यह सम्मान आ गया। मुझे यह सम्मान, अपमान जैसा लग रहा है। मंच आपका और माला-दुशाला मेरा, बात कुछ हजम नहीं हो रही।’ गिरधर जी अत्यंत निराश भाव से बोले-‘तो फिर रहने दो शर्मा। मैं किसी और से बात करता हूं। मैं तो इसलिए तुम्हारे पास आया था कि घर के आदमी हो। तुम्हारा सम्मान भी कभी नहीं हुआ। फूल-मालाओं से लदवा देता सार्वजनिक रूप से पीछे गया हुआ, किसने देखा है। मान-सम्मान के लिए तो लोग पता नहीं क्या-क्या जोड़-तोड़ करते हैं। तुम क्या पत्नी के आभूषण दांव पर नहीं लाया सकते? देखो, सभी जगह ऐसा होता है, पचास माहए लानी हैं, शॉल लाना है और दो सौ आदमियों के जलपान की व्यवस्था करनी है। कुल पांच हजार में ‘साहित्य शिरोमणि’ हो जाओगे।’ अब मैं सोच में पड़ गया हूं।

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

जाहिर है जब सम्पत्ति अल्लाह को समर्पित कर दी गई है तो उसकी सार संभाल तो इसी संसार के कुछ लोग अल्लाह की तरफ से करेंगे। अल्लाह की तरफ से सार संभाल करने का अधिकार इन ‘कुछ’ लोगों को कौन देता है, यह प्रश्न सदा विवाद का विषय बना रहेगा। अल्लाह को दान की गई इन सम्पत्तियों से जो आमदन होती है उसका कुछ हिस्सा, इन सम्पत्तियों की सार संभाल करने वाला व्यक्ति अपने मेहनताने के एवज में अपने पास भी रख सकता है। इसलिए विवाद बढ़ता रहता है। जिसके नियंत्रण में अल्लाह को दी गई यह सम्पत्ति आ जाती है, वह इसे छोड़ना नहीं चाहता। 1947 में अंग्रेजों के चले जाने के उपरांत कांग्रेस ने सरकार बनाई तो उसने 1954 में वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया। सरकार को पता चला कि इस देश की जमीन का बड़ा हिस्सा वक्फ में अल्लाह को दिया जा चुका है। कहा जाता है कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद देश की सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के नाम पर अल्लाह को दी जा चुकी है। वक्फ के पास इस समय देश की आठ लाख एकड़ से अधिक जमीन है। बोर्ड की अनुमानित संपत्ति 1.2 लाख करोड़ रुपए है। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थी। इस मसले की जड़ तक जाना जरूरी है। दरअसल इस देश में अरबों, तुर्कों व मुगलों के हमले 712 में शुरू हो गए थे। 1200 तक आते-आते उन्होंने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और उसमें से कुछ हिस्सा अलग-अलग समय में अल्लाह को भी दे दिया। व्यावहारिक रूप से अल्लाह को देने का मतलब मुल्ला मौलवियों को देना ही था। ये मुल्ला मौलवी इस देश के रहने वाले तो थे नहीं, बल्कि ये भी इन्हीं हमलावरों के साथ मध्य एशिया से आए थे। एटीएम (अरब, तुर्क, मुगल) के राज में देसी मुसलमानों (डीएम) को लगता था कि शायद मुल्ला मौलवी वक्फ की इस सम्पत्ति से, उनकी हालत सुधारने के लिए भी ध्यान देंगे, लेकिन न तो ऐसा हुआ और न ही आगे होने की सम्भावना थी, क्योंकि 1954 में वक्फ बोर्ड बन जाने से सारे अधिकार कानूनी रूप से एक वर्ग विशेष के हाथों में दे दिए गए। देसी मुसलमान, जिन्हें एटीएम मूल का मुसलमान पसमांदा, अरजाल, अलजाफ, न जाने और कितने निंदनीय शब्दों से

दृष्टि कोण

भारत

वर्ष में इन दिनों इतिहास पुनर्लेखन लगातार बहस का विषय बना हुआ है। इतिहास लेखन में आमतौर पर वस्तुपरक लेखन का दावा किया जाता है, किन्तु यह दावा आंशिक रूप से ही सही है। इतिहास लेखन में व्यक्तिपरक लेखन की संभावना हमेशा बनी रहती है। ज्यादातर इतिहास विजेताओं द्वारा लिखे गए, इसलिए उनमें विजेताओं का महिमामंडन या उनके पक्ष को सही ठहराने की वृति हमेशा बनी ही रहती है। किन्तु जहां भी किसी पक्ष से असंबद्ध लेखकों द्वारा लेखन हुआ वहां-वहां इतिहास की वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता की कसौटी पर तुलनात्मक रूप से खरी उतरती है। भारतवर्ष का आधुनिक प्रचलित इतिहास मुस्लिम आक्रांताओं, अंग्रेजी शासन और वाम विचारधारा से जुड़े इतिहासकारों की देन है, जिसमें बहुत मेहनत से काम हुआ है। किन्तु उसमें निष्पक्षता का स्तर असंदिग्ध नहीं है। क्योंकि उन सभी के अपने-अपने निहित स्वार्थ हैं या भारत को देखने की अपनी विशिष्ट दृष्टि है, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। मुस्लिम आक्रांता ऐसे देशों से आए थे जहां खाने, जीने के साधन पर्याप्त मात्र में उपलब्ध नहीं

थे। इसलिए लूटे के अतिरिक्त दूसरा लक्ष्य था कि भारत में ही बस कर यहां की सुख-सुविधाओं का अपनी इच्छा से उपभोग कर सकें। उनके लिए दूसरे देशों में जाकर इस्लाम को फैलाना भी पुण्य का काम था, इसलिए अनेक देशों को जीत कर इस्लाम फैलाने के लिए भी उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और अपने इस लक्ष्य को जायज ठहराने की दृष्टि से इतिहास लेखन हुआ। अंग्रेजों की दृष्टि तत्कालीन ईसाई दृष्टि थी, जिसके अनुसार जो भी लोग ईसाइयत का ज्ञान नहीं रखते और मानते वे लोग बर्बरता में फंसे हुए हैं, उनकी मुक्ति के लिए हमें वहां ईसाइयत का संदेश लेकर जाना है। यह हमारा धार्मिक कर्तव्य है। हालांकि यूरोप का ठंडा जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव भी उसके पीछे का कारण रहा है, जिस कमी को पूरा करने के लिए उपनिवेशवाद का सहारा लिया गया और तमाम एशियाई, अफ्रीकी और अमरीकी देशों पर कब्जा कराने की मुहिम शुरू हुई और कुछ देशों की आबादी को पूरी तरह नष्ट करके खुद वहां के मालिक बन गए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया। जहां इस तरह का कब्जा करके पूरी आबादी को ही प्रतिस्थापित करना संभव नहीं था, वहां

उन्होंने स्थानीय सभ्यताओं और संस्कृतियों को घटिया साबित करने और पाश्चत्य सभ्यता को स्थापित करके अपने शासनों को सुनिश्चित करने का कार्य किया। इतिहास लेखन का उनका कार्य इसी दृष्टि से किया गया। ज्यादातर परिकल्पनाएं जिनकी स्थापना की गई, वे उनके उपरोक्त लक्ष्यों को पूरा करने वाली थीं। बड़ी चालाकी से उन्होंने, जो तथ्य या घटनाएं उन्हें अपने उपयुक्त नहीं लग्ीं, उनका विलोपन कर दिया गया या अनदेखा किया गया। हालांकि उन्होंने तथ्यात्मकता और वस्तुपरकता को आधार बना कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की स्थापना की, किन्तु तथ्यों और घटनाओं की व्याख्या अपने यूरोपीय दृष्टिकोण से करने के कारण बहुत सी जाने या अनजाने गलतियां की जो उनके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जरूरी थीं। उदाहरण के लिए उनकी दयनीय स्थिति का झूठा चित्रण करके अपने आप को उन्नत साबित करने का काम नई शिक्षा द्वारा किया गया, जबकि धर्मपाल द्वारा इकट्ठे किए गए ब्रिटिश रिकॉर्ड के आंकड़ों से यह साबित होता है कि उनका यह कथानक झूठा है। 1822-25 के मद्रास प्रेसीडेंसी में किए गए सर्वे के अनुसार उस समय भी प्रेसीडेंसी में 11575 स्कूल और

1094 कॉलेज थे जिनमें क्रमशः 157195 और 5431 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। जातिगत बनावट के बारे में भी हैरान करने वाले आंकड़े सामने आते हैं, जिनके अनुसार तमिल भाषी क्षेत्र में शूद्र और उससे निचली जातियों से संबंधित 70 से 80 फीसदी विद्यार्थी थे, उडिया क्षेत्र में 62 फीसदी, 54 फीसदी मलयालम भाषी क्षेत्रों में और 50 फीसदी तेलुगु क्षेत्रों में थे। ये ही बात यहां उपलब्ध तक्तनीकी ज्ञान के बारे में भी लागू होती है। उत्तरप्रदेश के अतिरंजी खेड़ा में 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी लोहे का प्रयोग होता था, किन्तु 18वीं शताब्दी सौई तक भी यहां बडिया किर्रम का स्टील बनाया जाता था, यह बात कम ही लोग जानते हैं। उस समय प्रति वर्ष उच्च कोटि का स्टील बनाने वाली कम से कम 10000 ऐसी भट्टियां कार्यरत थीं जो साल में बीस टन तक स्टील तैयार कर रही थीं। चंचक के इलाज के लिए इनुकुलेशन की जाती थी और प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अंग मरम्मत की जाती थी। सुश्रुत के सदियों बाद तक यह विद्या 18वीं शताब्दी तक मौजूद थी। यह भारतीय सेवा के तत्कालीन अफसर डा. बैरी द्वारा वर्णित पूना में उनके द्वारा देखे गए एक आपरेशन से पता चलती है।

कुछ अलग

मंच हमारा, माला तेरी...

जिस समय वे मेरे यहां आए, चिंता की लकरीं ललाट पर स्पष्ट रूप से दिख रही थीं। वे मेरे परमपिय थे। सो बोला-‘क्यों, क्या बात है? मेरे लायक कोई कार्य हो तो बताओ। इतने निश्चित होने की बात क्या है?’ वे और अधिक गमगीन हो गए। लगभग रुआंसे होकर बोले-‘शर्मा मुझे बचा लो। मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। मेरी इज्जत दांव पर लग गई है। तुम तो घर के आदमी हो, दूसरे से कह भी नहीं सकते।।’ मैंने कहा-‘गिरधर जी मामला क्या है? आपकी इज्जत के लिए मैं अपना इज्जत दांव पर लगा दूंगा, आखिर बात क्या है?’ गिरधर जी अपना मुंह मेरे कान के पास लाए और बोले-‘शर्मा अपनी संस्था का वार्षिक कार्यक्रम वर्ष बीतेने को आया, लेकिन हो नहीं पा रहा है। साफ बात है संस्था आर्थिक विषमता में जी रही है। इस वर्ष सम्मान समारोह नहीं हुआ तो सारी बात खाक में मिल जाएगी, दूसरा गुट बदनामी करने पर तुला है।’ मैंने कहा, ‘तो कहिए, मुझे करना क्या है?’ गिरधर जी बोले, ‘तुम ऐसा करो, इस वर्ष का सम्मान ले लो। मेरी और संस्था की नाक बच जाएगी।’ मैं उनकी बात पर हंस पड़ा और बोला, ‘इसमें गिरधर जी चिन्ता की क्या बात है? इस वर्ष का साहित्य शिरोमणि सम्मान में ले लूंगा। आप तो चिन्ता को त्यागो और सम्मान की तैयारी करो।’ गिरधर जी लगभग पसर से गए और मौन साध गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने फिर कहा-‘क्यों अब क्या बात है? मैं सम्मान ले लूंगा, मना थोड़े ही कर रहा हूं।’ शर्मा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। मैंने अभी कहा कि संस्था पूरी तरह दिवालिया

सरकार को पता चला कि इस देश की जमीन का बड़ा हिस्सा वक्फ में अल्लाह को दिया जा चुका है

वक्फ को लेकर उभरता विवाद



सम्बोधित करता है, अपने ही देश में अपनी ही सम्पत्ति अशराफ के हाथों लुटती देखता रहा। समय समय पर इस वक्फ अधिनियम में संशोधन होते रहे और एटीएम का शिंकजा और कसता गया। भारत के मुसलमानों में दो वर्ग हैं, पहला वर्ग उन मुसलमानों का है जिनके वंशज इस मुल्क में हमलावर के रूप में आए थे। यह वर्ग एटीएम कहलाता है। दूसरा वर्ग उन मुसलमानों का है जो यहीं के लोग हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से हमलावरों के मजहब में शामिल हो गए थे। उन्हें देसी मुसलमान या डीएम कहा जाता है। इस मुल्क में यदि कोई सम्पत्ति अल्लाह के नाम पर दान भी की जाती है तो वह यकीनन देसी मुसलमानों की ही हो सकती है। हमलावर अरब, तुर्क या मुगल अपने देशों की जमीन या सम्पत्ति तो उठाकर लाए नहीं थे जिसे उन्होंने हिन्दुस्तान में आकर वक्फ के नाम कर दिया। वक्फ का असूल है कि जो सम्पत्ति वक्फ को जाती है वह उसकी अपनी सम्पत्ति होनी चाहिए। दूसरे की कब्जाई गई सम्पत्ति को वक्फ के नाम नहीं किया जा सकता। अब केवल उदाहरण के लिए यदि अपने वक्त में औरंगजेब ने कोई जमीन वक्फ की हो तो उसको वक्फ माना ही नहीं जा सकता क्योंकि वह उसके पूर्वजों द्वारा बलपूर्वक कब्जाई सम्पत्ति है। एक और उदाहरण लिया जा सकता है। दो फरीकों में किसी सम्पत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा है। पहले फरीक के कब्जे में वह सम्पत्ति है लेकिन उसको लग रहा है कि वह केस हार जाएगा। इसलिए वह केस का फैसला आने से पहले ही वह सम्पत्ति मौलवी से मिल कर फरीक के नाम कर देता है। वक्फ बोर्ड की दलदल में फंस गई यह सम्पत्ति अब वापस असली मालिक को नहीं मिल सकती। यह नियम बना पंखा है कि एक बार वक्फ के नाम हो चुकी सम्पत्ति वापस नहीं हो

इतिहास पुनर्लेखन का काम कैसे हो?

देश

दुनिया से

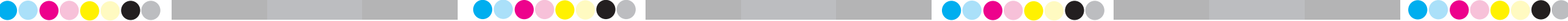
पूर्वोत्तर में सुरक्षा चुनौती को गंभीरता से लेने की जरूरत

यहां मेरा उद्देश्य हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र की अंदरूनी स्थिति को उजागर करना है। आज के अखबारों ने मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बोरेन सिंह का कथित बयान भी छापा है, जिसमें उन्होंने दिवंगत पीए संगमा द्वारा संसद में 2014 में दिए एक भाषण का एक वीडियो साझा किया है, संगमा उसमें कथित तौर पर कुकी लैंड क्षेत्र में अन्य छोटे-छोटे राज्य बनाने का समर्थन कर रहे हैं। बोरेन सिंह ने कहा कि अभी मणिपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राज्य को अस्थिर किया जा सके। इस बयान पर मेघालय के मुख्यमंत्री और पीए संगमा के बेटे ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने पिता का बचाव किया है। मैंने भविष्य में बांग्लादेश (और पाकिस्तान) की संभावित भूमिका और हमारी अपनी आंतरिक खींचतान (महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों द्वारा दिए जा रहे असंयमित बयानों को देखते हुए) को सामने लाने के लिए गहरे उत्तरकर मनन किया है। 2023 तक और मणिपुर में हिंसा की शुरुआत होने तक, दशकों की अशांति और हिंसा के बाद पूर्वोत्तर में शांति कायम थी। नगालैंड में युद्ध विराम था और असम, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में निर्वाचित

बहाल हुई है, लेकिन सामाजिक ताना-बाना बिखर चुका है और चुप्पी ही एकमात्र संवाद है। पहाड़ी लोग अपनी पुरानी जीवन शैली में वापस नहीं जा पा रहे। हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं, जिसे एक भड़काऊ बयान विस्फोट में बदल सकता है। समुदायों और सरकार के बीच बातचीत की प्रक्रिया शुरुआती दौर में आरंभ नहीं की गई और राज्य सरकार ने जोर-जबरदस्ती वाले तरीकों का इस्तेमाल करना चुना, जो विफल रहा। पूर्वोत्तर में स्थिति संभालने लिए उच्चतम स्तर की राजनीतिक सूझबूझ और राजनीति कौशल की आवश्यकता है। हमें पहले स्थिति को बिगड़ जाने देना और फिर आग बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं अन्य राज्यों पर एक नजर डालना चाहूंगा- मिजोरम में लंबे समय से शांति है, लेकिन अब कुछ आशंकित करने वाले संकेत दिखाई देने लगे हैं। जैसा कि मीडिया में बताया गया है कि भारत सरकार ने मिजोरम सरकार से कहा है कि वह प्यांमार से आने वाले रोहिंग्याओं को शरण न दे और उनके लिए शिविर न बनाए। हालांकि, बताया जाता है कि मिजोरम ने फिर भी ऐसे शिविरों की स्थापना कर रखी है। इसी तरह, मिजोरम सरकार से मणिपुरी शरणार्थियों को भी न लेने और शिविर न लगाने की हिदायत दी गई। हालांकि, उसने वहां के लोगों को भी



मेघालय और नगालैंड में भी गुंजती है, इसलिए एक राज्य में जो घटित होता है उसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से प्यांमार और मणिपुर एवं मिजोरम के बीच हिंसा नीत संबंध रहा है, शरणार्थी संकट के मद्देनजर इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इस क्षेत्र में एक खिलाड़ी बनने के लिए बेताब है और उस पर रणनीति बनाने समय चीन को ध्यान में रखना होगा। मणिपुर में संघर्ष की मौजूदा दौर में मणिपुर एवं मिजोरम, दोनों जगह, भूमिगत तत्व सक्रिय हो गए हैं, सीमा पार करने और तस्करी में भी वृद्धि हुई है। भूकंप के बाद प्यांमार से लोगों और भूमिगत तत्वों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। सीमा प्रबंधन में सुधार करना होगा। कुल मिलाकर, पूर्वोत्तर में बाहरी और आंतरिक, दोनों ही स्थितियों पर चिन्ता कर, पर बारीकी से नजर रखने और निर्णय लेने की आवश्यकता है। इन स्थितियों के नियमित रणनीतिक प्रबंधन को राज्य स्तर पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि उनका नजरिया एक सीमा तक होता है। समय बहुत अहम होता है और ऐसी नीति की आवश्यकता है जिसमें उद्देश्य स्पष्ट हो और उनकी प्राप्ति हेतु रणनीतियां एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने के तरीके और साधन निर्धारित हों।





भारत ने नेपाली वस्तुओं के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया

काठमांडू

बैकॉक, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

नालांदार चादर और प्लाई लकड़ों सहित विभिन्न वस्तुओं पर भारतीय मानक प्रमाण पत्र ब्यूरो के नए सिरे से लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है। बैकॉक में शुक्रवार को शाम को दोनों देशों के प्रधानमंत्री को साइडलाइन मुलाकात से पहले भारत की तरफ से प्रतिबंध को

हटाना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने शुक्रवार को बताया कि भारत को नेपाली वस्तुओं के निर्यात और भारतीय बाजारों में माल की बिक्री और वितरण के लिए सुविधा प्रदान करने के भारत सरकार से किए गए आग्रह को उधर से स्वीकार कर

लिया गया है। उन्होंने कुछ महीने पहले अपनी भारत यात्रा के दौरान भारतीय समकक्ष पीयूष गोयल के साथ नेपाल की वस्तुओं पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए आग्रह किया था। मंत्री भंडारी ने कहा कि गत 11 और 12 जनवरी को नेपाल-भारत वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई थी। इसके बाद भारतीय पक्ष ने

समस्याओं को हल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। भारत ने सीमेंट, नालीदार चादरें, सैनिटरी पेड और जूते सहित वस्तुओं के निर्यात पर वीआईएस को अनिवार्य कर दिया है।

नेपाल ने पांच महीने से भारत को सीमेंट का निर्यात रोक दिया था और एक महीने पहले से प्लाईवुड के आयात पर भी रोक लगा दी थी।

भारत के नए प्रावधानों के मुताबिक वीआईएस का नवीनीकरण नहीं करने पर नेपाल की वस्तुओं का आयात नहीं किया जा सकता है। बैकॉक में शुक्रवार को शाम को दोनों देशों के प्रधानमंत्री की साइडलाइन मुलाकात से पहले भारत की तरफ से प्रतिबंध को हटाना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

न्यूज़ ब्रीफ

बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ओली ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर दिया जोर



काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के तीन स्तंभ समृद्धि, लचीलापन और खुलापन न केवल सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं, बल्कि नेपाल की समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली की राष्ट्रीय आकांक्षा के साथ गहराई से प्रतिबिम्बित भी होते हैं। थाईलैंड के बैकॉक में शुक्रवार को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि बिम्स्टेक को न केवल बदलते समय के साथ खुद को ढालना चाहिए, बल्कि हमारे क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के अवसर का भी लाभ उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र का निर्माण हमारी क्षमता को और अधिक उपयोग करने और हमारे पास मौजूद संसाधनों के सही उपयोग के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह मानते हुए कि हमारे क्षेत्र की सभी अर्थव्यवस्थाएं समान नहीं हैं, हमें सदस्य राज्यों को विशेष जरूरतों के साथ तरजीही समर्थन देना चाहिए, ताकि वे आम समृद्धि साझा कर सकें। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने पूरी मानवता के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा कर दिया है, इसलिए नेपाल की विशेष जिम्मेदारी बनती है। ओली ने कहा कि हमारे उच्च हिमालय बारहमासी जल टावर और एशिया के कूलिंग स्टेशन हैं।

कैलासा: एक भगोड़े का दिव्य धोखा बोलीविया में भूमि हड़पने की साजिश



लापाज। स्वघोषित 'संप्रभु राइट', 'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा', जिसने अपने पासपोर्ट, 'कास्मिक सविधान' और आधिकारिक मुद्रा के साथ दुनिया का ध्यान खींचा लेकिन अब धोखाधड़ी और भूमि हड़पने के आरोपों से घिरा हुआ है। इसका नेता नित्यानंद, जो एक भगोड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है, अलौकिक शक्तियों का दावा करता है। लेकिन उसकी सदिग्ध गतिविधियां अब उजागर हो रही हैं। हाल ही में बोलीविया में हुई घटनाओं ने उसके दावों की पोल खोल दी है। जहां अधिकारियों ने 'भूमि तस्करी' के आरोप में कैलासा के 20 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। बोलीविया के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से कैलासा को मान्यता नहीं देने की घोषणा की है। बोलीवियाई मीडिया द्वारा की गई जांच में नित्यानंद के अनुयायियों द्वारा स्वदेशी समूहों, जिसमें बाउरे समुदाय शामिल है, से व्यापक भूमि पट्टे हासिल करने के प्रयासों का खुलासा हुआ। बाउरे नेता पेद्रो गुआसिको ने बताया कि जंगल की आग के बाद सहायता की प्रारंभिक पेशकशें एक समस्याग्रस्त 1,000 साल के पट्टा समझौते में बदल गईं। कैलासा अधिकारियों ने 25 साल के समझौते में वार्षिक भुगतान के रूप में लगभग 200,000 डॉलर का वादा किया था, लेकिन बाद में अनुबंध की 1,000 साल तक बढ़ा दिया गया और इसमें वायु क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण के अधिकार शामिल थे। गुआसिको ने स्वीकार किया कि उनके समूह ने हस्ताक्षर करने की गलती की।

इजराइली सेना में फिर बरसाए रिहायशी इलाके व स्कूल पर बम, कई लोगों की मौत

दीर अल बलाह। इजराइली लड़ाकू जेट ने गुरुवार को गाजा पट्टी में कहर बरपाया है। इजराइली हवाई हमलों



में गाजा में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई। इसमें उत्तरी गाजा के स्कूल पर हवाई हमला भी शामिल है, जिसमें शरण लिए 33 लोग मारे गए हैं। स्कूल पर हुई बमबारी में 70 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट में फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल के दिनों में इजराइल ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इजराइली सेना ने कहा है कि उसने आक्रामक कार्रवाई तेज की है जिसका इरादा हमला पर नया दबाव डालना और उसे खदेड़ देना है। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि गाजा शहर के तुफाह में स्थित एक स्कूल से 14 बच्चों और पांच महिलाओं के शव बरामद किए गए लेकिन मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि 70 घायलों में कुछ की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। उन्होंने अस्पताल के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि निकटवर्ती हिजाय्याह इलाके में घरो पर हुए हमलों में 30 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। इजराइली सेना ने कहा कि उसने गाजा सिटी इलाके में हमला कमांड और कंट्रोल सेंटर पर हमला किया है।

ऐसा क्या करने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप कि एच 1बी वीजा धारकों की दिल की धड़कनें बढ़ी

वॉशिंगटन, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से दुनिया में हलचल है। वह एक ओर कुछ देशों पर टैरिफ अटैक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सख्ती दिखाते हुए अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। अब उनके सख्त इमिग्रेशन कानून से वहां रह रहे हजारों एच-1बी वीजा धारक आईटी पेशेवरों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें अमेरिका छोड़ने का डर सता रहा है। इसी खौफ के बीच गूगल और अमेजन जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों ने अपने एच-1बी वीजा धारक कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे अमेरिका ना छोड़ें।

इन मशहूर कंपनियों को डर है कि शायद ट्रंप प्रशासन अमेरिका छोड़ने के बाद हजारों प्रवासी एच-1बी वीजा धारकों को दुबारा लौटने को इजाजत ना दे। इसके बाद हजारों भारतीय सहित कई देशों के एच-बी वीजा धारक पेशेवर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता के दौर में जी रहे हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी आशंका है कि आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन में हार्ड स्किल्ड पेशेवरों के वीजा अस्वीकृति की दर बढ़ सकती है, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में पैदा हुए लोगों के जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के ट्रंप प्रशासन की कोशिशों से भी एच-1बी वीजा धारकों में डर है। उन्हें लग रहा है कि उनके भविष्य में अपनी अमेरिकी नागरिकता खो सकते हैं।

बता दें कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम कंपनियों को विशेषज्ञता वाले पदों पर अस्थायी रूप से विदेशी पेशेवरों की नियुक्ति को इज्जत देता है। भारत की विशेषरूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां इस कार्यक्रम से काफी लाभान्वित हुई हैं। हर साल लांटरी



रनवे खूटे ही लगा तेज झटका, उछलने लगा प्लेन, टर्की में फंसे 250 पैसंजर

लंदन। 260 यात्रियों को लेकर लंदन से मुंबई जा रही वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट वीएस 358 के यात्रियों को बताया गया कि टर्की के दियारबाकिर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला है। चूंकि, लैंडिंग की वजह मेडिकल इमरजेंसी बताई गई थी, लिहाजा चाह कर भी कोई कुछ नहीं कह सकता था। पैसंजर की जान यह जानकर भी हलक में अटक गई कि जिस दियारबाकिर एयरपोर्ट पर उनका प्लेन लैंड होने वाला है, वह कोई कामर्शियल एयरपोर्ट नहीं, बल्कि टर्किश आर्मी की एयर बेस है। कुछ मिनटों के बाद प्लेन रनवे के करीब पहुंच चुका था। वहीं, प्लेन ने जैसे ही रनवे से टच किया, पैसंजर्स को एक तेज झटका लगा। प्लेन किसी गैद की तरफ रनवे पर कुछ देर तक उछलता रहा। प्लेन में पैदा हुए इन हालात ने हर किसी को दहशत से भर दिया। किसी तरह प्लेन टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुंचने में कामयाब रहा। और, इसी के साथ पैसंजर्स के लिए परेशानियों और दर्द से भरे एक नए सफर की शुरुआत हो गई। शुरुआत में सभी को यही उम्मीद थी कि यह बस एक छोटो-सा उठराव है। लेकिन प्लेन से बाहर निकलने के बाद सभी को पता चला कि हार्ड लैंडिंग की वजह से प्लेन के टायर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लिहाजा अगला प्लेन आने तक सभी पैसंजर को इसी एयरपोर्ट पर इंतजार करना होगा। बीते 24 घंटे से मुंबई आ रहे 250 पैसंजर इसी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दियारबाकिर एयरपोर्ट पर हालात बद से बदतर हो गए। पैसंजर्स का दावा है कि वहां का एयरपोर्ट स्टाफ न अंग्रेजी समझते थे, न हिंदी। यहां न कोई हमें समझा रहा है, न कोई रास्ता दिखा रहा है। हम भ्रमित और असहाय हैं। छोटे-छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, बुजुर्गों की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। पैसंजर्स एयरपोर्ट की ठंडी फर्श पर रात बिताने को मजबूर हैं। न कोई एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव है, न कोई मदद करने वाला। हालांकि इस बीच वर्जिन अटलांटिक ने आश्वासन दिया है कि होटल और दूसरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।



नाटो बैठक में अमेरिकी विदेशमंत्री से हाथ मिलाते हुए लार्स लोकी रेसमुसन



बेल्जियम में डेनमार्क के विदेशमंत्री लार्स लोकी रेसमुसन नाटो बैठक में अमेरिकी विदेशमंत्री से हाथ मिलाते हुए।

प्रधानमंत्री मोदी की बैकॉक में म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात, भूकंप त्रासदी पर संवेदना जताई

बैकॉक, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने थाईलैंड की राजधानी बैकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। उन्होंने हाल ही में आए भूकंप के कारण हुई जान-माल की हानि पर एक बार फिर संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी एक्स पोस्ट पर कहा, भारत इस कठिन समय में म्यांमार के भाइयों और बहनों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

उन्होंने लिखा, हमने भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावत्रा से मुलाकात की।

उन्होंने रक्षा, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में भारत और थाईलैंड के बीच सहयोग की अपार संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर शिनावत्रा से हुई मुलाकात का विवरण साझा किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री श्री थाकसिन शिनावत्रा से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्हें शासन और नीति निर्माण से संबंधित



मामलों में व्यापक अनुभव है। वे भारत के बहुत अच्छे मित्र भी हैं और अटल जी के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री शिनावत्रा और मैंने भारत-थाईलैंड सहयोग और इससे हमारे

संबंधित देशों के लोगों को किस तरह लाभ होता है, इस बारे में विस्तार से बात की। हमने रक्षा, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में अपार संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति येओल को संवैधानिक न्यायालय ने बर्खास्त किया

सियोल, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल को पिछले साल की गई अपनी अल्पकालिक मार्शल लॉ की घोषणा के लिए अपने पद से हाथ धोना पड़ा। उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। संवैधानिक न्यायालय ने महाभियोग का सामना कर रहे येओल को उनके पद से तत्काल हटाने की घोषणा की। संवैधानिक न्यायालय ने शुक्रवार सुबह 11:22 बजे अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनकर संवैधानिक न्यायालय के बाहर एकत्र लाखों लोग खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोकतंत्र की जीत का जश्न मनाते हुए न्यायालय के पक्ष में नारे लगाए।



कोरिया टाइम्स अखबार के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मून ह्युंग-वे ने राष्ट्रपति यून सुक येओल को पद से तत्काल हटाने की घोषणा की। जैसे ही न्यायालय के बाहर लगी बड़ी टीवी स्क्रीन पर महाभियोग की सजा शब्द दिखाई दिया, लोग उछल पड़े। एक-दूसरे को गले लगाया। कई लोग तो लोकतंत्र की जीत पर फूट-फूट कर रोने लगे। इस दौरान यह लोग काफी देर तक नारा लगाते रहे- विजय! विजय! लोकतंत्र अमर रहे। यह देखकर अपदस्थ नेता यून सुक येओल ने कहा, मुझे सच में खेद है और दिल टूट गया है कि मैं आपको उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका।

संवैधानिक न्यायालय ने राष्ट्रपति येओल के महाभियोग को बरकरार रखा। इसके बाद उन्हें तत्काल पद से हटा दिया गया। राष्ट्रपति को पद से हटाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। संवैधानिक

न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने 8-0 के मत से पक्ष में मतदान किया। उल्लेखनीय है कि नेशनल असेंबली ने 111 पहले येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। येओल पर तीन दिसंबर को मार्शल लॉ घोषित करने के लिए उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मून ह्युंग-वे ने सुबह 11 बजे फैसला पढ़ना शुरू किया। उन्होंने 11:22 बजे कहा कि येओल को तत्काल राष्ट्रपति पद से हटाने का फैसला किया गया है।

इससे पहले मार्च 2017 में पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे के महाभियोग के बाद आठ वर्षों में दक्षिण कोरिया में किसी मौजूदा राष्ट्रपति की यह पहली बर्खास्तगी है। संविधान के अनुच्छेद 68 के तहत, न्यायालय के फैसले के 60 दिनों के भीतर नया राष्ट्रपति चुनाव होना चाहिए। संभावना है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव तीन जून या उससे पहले होगा। अब येओल और उनकी पत्नी किम कीन ही को मध्य सियोल के हन्मा-डोंग में राष्ट्रपति निवास खाली करना होगा।



हैदराबाद पर मिली जीत के बाद केकेआर के उपकप्तान वेंकटेश अय्यर ने कहा-सकारात्मक लेकिन सही इरादे दिखाना जरूरी

कोलकाता,04 अप्रैल (एजेंसियां)। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के उप-कप्तान वेंकटेश अय्यर ने टाटा आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) पर मिली 80 रनों की धमाकेदार जीत के बाद टीम के प्रदर्शन पर विस्तार से बात की। उन्होंने मैच की स्थितियों को पढ़ने और उसी के अनुसार ढलने के महत्व को रेखांकित किया। अय्यर ने 29 गेंदों में 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 60 रनों की तेजतर्रार पारी खेली, जिससे केकेआर ने इंडन गार्डन्स में पिछले सीजन के फाइनल की पुनरावृत्ति में 200 रनों का मजबूत

स्कोर खड़ा किया। अय्यर ने मैच के बाद कहा, आक्रामकता का एक मूल लेकिन महत्वपूर्ण अर्थ है सकारात्मक लेकिन सही इरादा दिखाना, अगर हमारी टीम 50 पर 6 है और मैं तब भी हर गेंद को हिट करने जाऊं, तो वह भले ही सकारात्मक लगे, लेकिन सही नहीं है। स्मार्ट क्रिकेटर कहलाने के लिए जरूरी है कि हम स्थिति को समझें और फिर प्रतिक्रिया दें। अय्यर ने स्पष्ट किया कि केकेआर के लिए आक्रामकता का मतलब हर गेंद पर बाउंड्री मारना नहीं है। आक्रामकता का अर्थ है परिस्थितियों को समझना और उन्हें अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए,

यह जानना। उन्होंने कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा बल्लेबाज अंकुष रघुवंशी को भी सराहना की, जिनकी सलाह ने उन्हें पिच को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। रहाणे और अय्यर ने 51 गेंदों में 81 रनों की साझेदारी की, जिसमें रहाणे ने 38 रन बनाए और रघुवंशी ने अर्धशतक जमाया। अय्यर ने कहा, टाइमआउट के दौरान मुख्य बातचीत अजिंक्य और अंकुष द्वारा की गई। उन्होंने यह समझाया कि यह पिच इतनी आसान नहीं है कि आते ही हिटिंग शुरू कर दें। आपको थोड़ा समय लेना होगा। केकेआर की बल्लेबाजी रणनीति में अय्यर और रिकू सिंह ने आधार तैयार किया, जिसके बाद अंतिम ओवरों में आक्रमण की योजना थी। अय्यर ने कहा, मेरे पास यह लक्ष्यी है कि हमारे पास रिकू, रमनदीप और रसेल जैसे बल्लेबाज हैं। अगर मैं कुछ गेंदें लेता हूं, तो भी हम उसे कवर कर सकते हैं। हमारे पास एक इंजन रूम है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकता है। एसआरएच की अत्यधिक आक्रामक बल्लेबाजी रणनीति पर बात करते हुए, जिसे केकेआर के गेंदबाजों - विशेषकर वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती (तीन-तीन विकेट) - ने धराशायी कर दिया।

न्यूज ब्रीफ

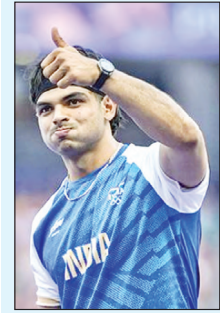
हॉपमैन कप मिश्रित टीम टेनिस टूर्नामेंट 16 से 20 जुलाई तक, इटली करेगा मेजबानी



बारी (इटली)। प्रतिष्ठित हॉपमैन कप का आयोजन इस वर्ष 16 से 20 जुलाई तक इटली के बारी शहर में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट विंबलडन के एक हफ्ते बाद आयोजित होगा। इस मिश्रित टीम टूर्नामेंट में इटली, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, कनाडा और गत विजेता क्रोएशिया की टीमें हिस्सा लेंगी। हॉपमैन कप में हर टीम में एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी शामिल होता है। प्रत्येक टाई में एक पुरुष एकल, एक महिला एकल और एक मिश्रित युगल मैच खेला जाता है। यह टूर्नामेंट एटीपी या डब्ल्यूटीए रैंकिंग अंक प्रदान नहीं करता। मेजबान इटली की ओर से जैस्मिन पाओलिनी और फ्लोरिया कोबोली खेलेंगी। अन्य देशों की टीमों की घोषणा अभी नहीं हुई है। पाओलिनी पिछले साल फ्रेंच ओपन और विंबलडन की महिला एकल उपविजेता रही थीं और उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सारा पारानी के साथ महिला युगल का स्वर्ण पदक भी जीता था। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज हैरी हॉपमैन के नाम पर शुरू हुआ यह टूर्नामेंट 1989 से 2020 तक लगातार खेला गया। 2023 में इसे फ्रांस में दोबारा शुरू किया गया था, जहां क्रोएशिया के डोना वेकिच और बोर्ना चोरिच की जोड़ी ने खिताब जीता था। करीब तीन दशक तक यह टूर्नामेंट पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) में नए साल की शुरुआत में आयोजित होता रहा। पिछले साल यह टूर्नामेंट फ्रांस के नीस में होना था, लेकिन ओलंपिक के नजदीक होने के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। बारी में इसका आयोजन इटली के व्यस्त टेनिस कैलेंडर में एक और आयोजन को जोड़ता है, जहां मई में इटालियन ओपन, और नवंबर में एटीपी फाइनल्स व डेविस कप फाइनल्स भी आयोजित होते हैं।

पंचकूला में होगा पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक अंतरराष्ट्रीय भाला फेक प्रतियोगिता

नई दिल्ली। हरियाणा के पंचकूला में 24 मई को पहली बार नीरज चोपड़ा क्लासिक (एनसी क्लासिक)



प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विश्व एथलेटिक्स ने गुरुवार को इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय भाला फेक प्रतियोगिता की पुष्टि की है। यह प्रतियोगिता वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड कैटेगरी इवेंट होगी, जो इसे विश्व

चैंपियनशिप के लिए एक महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन स्पर्धा बना देगी। इस इवेंट में शीर्ष अंतरराष्ट्रीय भाला फेक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। प्रतियोगिता का आयोजन पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में किया जाएगा। वर्तमान विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा अपने 2025 सीजन की शुरुआत 16 मई को कतर में होने वाले दोहा डायमंड लीग से करेंगे। यह इवेंट नीरज चोपड़ा क्लासिक से ठीक एक सप्ताह पहले होगा। नीरज ने भारत में अपना पिछला इवेंट 2024 फेडरेशन कप में खेला था, जहां उन्होंने 82.27 मीटर भाला फेककर स्वर्ण पदक जीता था।

दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाले आईपीएल इतिहास के एकमात्र गेंदबाज हैं कामिंदू मुम्बई।

मुम्बई। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेल रहे ऑफ स्पिनर कामिंदू मेंडिस दोनों ही हाथों से गेंदबाजी करने के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने इंडन गार्डन में हुए पहले ही मैच में दोनों हाथों से गेंदबाजी करते हुए विकेट लेकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। वह आईपीएल इतिहास में ऐसा करने वाले पहले पुरुष गेंदबाज हैं। मेंडिस को टीम ने केवल 75 लाख रूपए में खरीदा पर उनका प्रदर्शन इससे कहीं अच्छा रहा है। वह श्रीलंका की टीम के लिए तीनों प्रारूपों में खेलते हैं। वहीं घरेलू क्रिकेट में वह कोलंबो क्रिकेट क्लब में शामिल हैं। मेंडिस ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत अक्टूबर 2018 में टी20 प्रारूप में इंग्लैंड के खिलाफ की थी। इसके बाद से ही वह टेस्ट और एकदिवसीय में भी श्रीलंका की ओर से खेलते रहे हैं। वह गेंदबाजी के साथ ही अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड भी हैं। मेंडिस टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के बाद से ही 8 मैचों में 50 से अधिक रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने डेब्यू के बाद लगातार 8 टेस्ट मैचों में 50 से अधिक रन बनाए हैं। यह रिकॉर्ड उन्होंने साल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ गॉल टेस्ट में बनाया था। मेंडिस ने मात्र 13 टेस्ट पारियों में 5 शतक लगाये हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ दो-दो। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ एक शतक लगाया है। इससे वह युवा टेस्ट बल्लेबाजों में शीर्ष पर पहुंच गये हैं। इस क्रिकेटर ने 12 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में 74.72 की औसत से 1,184 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं।

लखनऊ ने मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हराया

सूर्यकुमार की कोशिश गई बेकार



नई दिल्ली,04 अप्रैल (एजेंसियां)। लखनऊ सुपरजाइंट्स ने अपने घर में मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। लखनऊ की चार मैचों में से यह दूसरी जीत है। मैच में टॉस हारने के बाद लखनऊ सुपरजाइंट्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के खेल में 203 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में पांच बार की चैंपियन मुंबई ने आखिरी ओवर में 191 रन ही बना सकी। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की यह चार मैचों में से तीसरी हार है।

लखनऊ के खिलाफ एकाना क्रिकेट स्टेडिय में लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत

कुछ खास नहीं रही थी। मुंबई के दोनों ओवर बल्लेबाज विल जैक्स और रयान रिक्लेटन जल्दी आउट हो गए। इसके बाद मुंबई के लिए नमन धीर और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर मोर्चा संभाला। नमन धीर मुंबई के लिए 24 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने सधी हुई बैटिंग करते हुए टीम के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचाया। सूर्यकुमार यादव के आउट होने के बाद हार्दिक पंड्या बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन बल्लेबाजी में वह टीम के लिए संघर्ष करते हुए दिखे।सूर्यकुमार के आउट होने के बाद तिलक वर्मा और हार्दिक की

जिम्मेदारी थी कि वह मैच को फिनिश करें, लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने आखिर के तीन ओवर में दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। लखनऊ सुपरजायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर आठ विकेट पर 203 रन बनाये। एलएसजी ने के लिए मिचेल मार्श ने 31 गेंद में 60 जबकि एडेन मारक्रम ने 38 गेंद में 53 रन का योगदान दिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने चार ओवर में 36 रन देकर पांच विकेट लिए।

सर्बिया में फीफा प्रेसीडेंट गियानी इनफेंटिनो व यूईएफए प्रेसीडेंट एलेक्सेंडर सीफेरिन

सर्बिया में फीफा प्रेसीडेंट गियानी इनफेंटिनो व यूईएफए प्रेसीडेंट एलेक्सेंडर सीफेरिन कांग्रेस के दौरान तस्वीरों के साथ पोज देते हुए।

अनुभवी पिस्टल शूटर राही सरनोबत ने बताई जीवन के सबसे कठिन दौर से उबरने की कहानी

देहरादून,04 अप्रैल (एजेंसियां)। अनुभवी पिस्टल शूटर और दो बार की ओलंपियन राही सरनोबत ने राष्ट्रीय खेलों 2025 में जबरदस्त वापसी करते हुए महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। 34 वर्षीय राही के लिए यह जीत केवल एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि उनके जीवन के सबसे कठिन दौर से उबरने की कहानी है। हाउस ऑफ ग्लोरी पॉडकास्ट (गगन नारांग स्पोर्ट्स फाउंडेशन की पहल) के एक हालिया एपिसोड में राही ने अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की कि कैसे उन्होंने न्यूरोपैथिक पेन सिंड्रोम जैसी जटिल और रहस्यमयी बीमारी से लड़ाई लड़ी और अब एक बार फिर ओलंपिक पदक के सपने को जीने के लिए मैदान में उतरी हैं।

राही के बीमारा होने की शुरुआत 2022 में हुई, जब वे वर्ल्ड चैंपियनशिप के नेशनल कैप के लिए तैयारी कर रही थीं। अचानक उन्हें शरीर में जलन और तंत्रिकाओं में दर्द जैसी समस्याएं महसूस होने लगीं। कई टेस्टों के बावजूद कोई ठोस निदान नहीं मिला। उन्होंने बताया मैं बिस्तर पर लेट भी नहीं सकती थी, महीनों तक बैठकर सोती थी। बाद में न्यूरोलॉजिकल जांचों के बाद उन्हें न्यूरोपैथिक पेन सिंड्रोम का पता चला। उन्होंने कहा, इस बीमारी का न तो कोई निश्चित पैटर्न है, न ही कोई इलाज। यह हर व्यक्ति की



मेडिकल हिस्ट्री पर निर्भर करता है। यही बात इसे और भी डरावना बना देती है। राही ने बताया कि वे महीनों तक दिन में 17-20 घंटे सोती थीं, और बस छत को घूरी रहती थीं। उन्होंने कहा, मैं सामान्य जीवन नहीं जी पा रही थी, मैं बस वापस जिंदगी में लौटना चाहती थी, खेल तो बाद की बात थी। यह पहली बार नहीं था जब राही को खेल में वापसी करनी पड़ी हो। 2014 में उनकी शूटिंग हाथ की कोहनी में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया

था, जिससे उबरने में उन्हें सात महीने लगे। फिर उन्होंने वापसी करते हुए 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता और 2021 टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया, लेकिन राही के अनुसार इस बार की वापसी बिल्कुल अलग रही।

उन्होंने बताया, पिछली बार यह एक सामान्य चोट थी, जिसका तय इलाज और प्रक्रिया थी, लेकिन इस बार तो मैं सिर्फ सामान्य जीवन जीने की चाह रख रही थी। शूटिंग तो सोच में भी नहीं थी। ठीक होने की राह भी आसान नहीं रही। न्यूरोलॉजिस्ट ने उन्हें दर्द के बावजूद फिजियोथेरेपी शुरू करने की सलाह दी। उनकी पहली कसरत थी - 20 मिनट तक बैठकर एक टीवी शो देखना। लेकिन अत्यधिक थकान के कारण वे यह भी नहीं कर पाईं। फिजियोथेरेपिस्ट ने उनके साथ दिन में कई घंटे काम किया। आज राही खुद को एक बदली हुई एथलीट मानती हैं। उन्होंने कहा, अब मैं खुद के लिए खेलती हूं। अब यह दुनिया को कुछ साबित करने के लिए नहीं है। यह मेरा सपना है, जिसे एक कारण से मेरे अंदर डाला गया है। मैं इसे एक और मौका देना चाहती हूं।

उन्होंने अंत में कहा, अब खोने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं और भी साहसी बन गई हूं। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे उस व्यक्ति के रूप में याद करें जिसने चीजों को मुमकिन बनाया।

हीरो हॉकी इंडिया लीग ने भारत में 4.1 करोड़ से अधिक दर्शकों को किया आकर्षित

पुरुषों की लीग ने 3.29 करोड़ और महिलाओं की लीग ने 1.51 करोड़ दर्शकों को जोड़ा

नई दिल्ली,04 अप्रैल (एजेंसियां)। हीरो हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) 2024-25 की बहुप्रतीक्षित वापसी ने भारतीय हॉकी में एक नया अध्याय जोड़ते हुए देशभर में खेल के प्रति जुनून को फिर से जीवंत कर दिया है। सात साल के अंतराल के बाद पुरुषों की लीग की वापसी और पहली बार महिला लीग की शुरुआत ने इस संस्करण को ऐतिहासिक बना दिया। लीग की रिकॉर्ड तोड़ दर्शक संख्या और डिजिटल प्रभाव इस बात का प्रमाण हैं कि हॉकी आज भी लाखों भारतीयों के दिलों की धड़कन बनी हुई है। हीरो एचआईएल 2024-25 ने उम्मीदों से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया है। इस बार कुल 4.08

दर्शकों ने देखा, जबकि महिलाओं का सबसे लोकप्रिय मैच 29.2 लाख दर्शकों तक पहुंचा। भारत के अलावा 18 हॉकी खेलने वाले देशों में 50 लाख से अधिक दर्शकों ने टीवी और ओटीटी के माध्यम से लीग का आनंद लिया। इस बार लीग ने परंपरागत दर्शक वर्ग के अंतर को भी तोड़ा है। सामान्यतः पुरुष और महिला खेलों के दर्शकों में छह गुना तक का अंतर देखने को मिलता है, लेकिन हीरो एचआईएल ने इस सोच को बदल दिया। कई मौकों पर महिला मुकाबलों को भी पुरुष मुकाबलों के समान दर्शक मिले। 144 पुरुष मुकाबलों को 3.29 करोड़ दर्शकों (2.35 करोड़ टीवी पर और 94 लाख ओटीटी पर) ने देखा, वहीं 13 महिला मुकाबलों को 1.51 करोड़ दर्शकों (1.05 करोड़ टीवी पर और 45.9 लाख ओटीटी पर) ने देखा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिकोई ने कहा, हीरो एचआईएल 2024-25 की सफलता भारत में हॉकी के प्रति गहरे प्रेम का प्रतीक है। प्रशंसकों, ब्रांडों और प्रसारकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया लीग को अपार संभावनाओं की दर्शाती है। हम भविष्य में भी भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हीरो एचआईएल 2024-25 की सफलता भारत में हॉकी के प्रति गहरे प्रेम का प्रतीक है। प्रशंसकों, ब्रांडों और प्रसारकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया लीग को अपार संभावनाओं की दर्शाती है। हम भविष्य में भी भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सिर्फ टीवी और स्ट्रीमिंग ही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी एचआईएल की गुंज सुनाई दी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हॉकी इंडिया के 3,000 से अधिक पोस्ट्स पर 1 अरब से अधिक व्यूज दर्ज किए गए, जो एक सक्रिय और जीवंत हॉकी समुदाय का प्रमाण हैं। हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा, हीरो एचआईएल की वापसी केवल आंकड़ों की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्रशंसकों और खिलाड़ियों में जागे गए उत्साह के लिहाज से भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। महिला लीग की शुरुआत समावेशिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। हीरो हॉकी इंडिया लीग की यह सफलता टोक्यो ओलंपिक के बाद से हॉकी की बढ़ती लोकप्रियता को भी दर्शाती है, जहां पहले सप्ताह में हीरो की कुल 6.9 करोड़ दर्शकों में से 15.2 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की थी।





भारत के सेवा क्षेत्र में गतिविधि में उत्पादन और बिक्री में मामूली गिरावट

नई दिल्ली, 04 अप्रैल (एजेंसियां)।

भारत के सेवा क्षेत्र में गतिविधि में उत्पादन और बिक्री में मामूली गिरावट के साथ मार्च महीने में थोड़ी धीमी रही है, इसकी जानकारी शुक्रवार को एक मासिक सर्वेक्षण से मिली है। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सेवा कारोबारी गतिविधि सूचकांक फरवरी के 59.0 से घटकर मार्च में 58.5 पर आ गया है। क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के अनुसार, 50 से ऊपर अंक का

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग काफी हद तक उत्साहजनक रही

मतलब है कि गतिविधियों में विस्तार हो रहा है जबकि 50 से कम का आशय है कि संकुचन हो रहा है। एचएसबीसी के भारत के एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने इस संकेत को तर्कसंगत बताया, भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर मार्च 2025 में

58.5 रही है जो पिछले महीने से थोड़ा कम है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग काफी हद तक उत्साहजनक रही, हालांकि यह पिछले महीने की तुलना में क्रमिक रूप से कम रही। कोमत की दृष्टि से मार्च में तैयार माल शुल्क पर मुद्रास्फीति साढ़े तीन साल के निचले स्तर पर आई है।

सर्वेक्षण प्रतिभागियों के अनुसार, मार्च में सेवा अर्थव्यवस्थाओं में भर्तियों की गतिविधि में कमी आई है। उपभोक्ता सेवा कंपनियां मार्च

में सबसे अधिक उत्साहित रही हैं, उसके बाद वित्त एवं बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, तथा परिवहन, सूचना और संचार सेक्टर। इस दौरान, भारतीय निजी क्षेत्र की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि कंपनियों ने नए ऑर्डरों में वृद्धि का स्वागत किया है। एचएसबीसी इंडिया कम्पोजिट आउटपुट सूचकांक फरवरी के 58.8 से मार्च में सात महीने के उच्च स्तर 59.5 पर पहुंच गया है।

न्यूज़ ब्रीफ

व्हाइट हाउस के दस्तावेज में भारत पर शुल्क 27 से घटाकर किया गया 26 प्रतिशत



नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ के दस्तावेज में भारत पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को 27 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया है। शुल्क नी अप्रैल से लागू होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों के खिलाफ जवाबी शुल्क की घोषणा करते हुए एक चार्ट दिखाया था जिसमें भारत, चीन, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों पर लगाई जाने वाली नई शुल्क दरों का उल्लेख था।वार्ट के अनुसार, भारत ‘‘मुद्रा हेरफेर और व्यापार बाधाओं’’ सहित 52 प्रतिशत शुल्क लेता है और अमेरिका अब भारत से 26 प्रतिशत का रियायती जवाबी शुल्क वसूलेगा। हालांकि, व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में भारत पर 27 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने का जिक्र था लेकिन नवीनतम अद्यतन दस्तावेज में इसे घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि शुल्क के एक प्रतिशत कम होने का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

थॉमस कुक इंडिया के ब्रांड एंबेसडर बने कार्तिक आर्यन



मुंबई। विदेशी मुद्रा सेवा प्रदाता थॉमस कुक इंडिया ने बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन को अपने बॉर्डरलेस यात्रा कार्ड के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। कपनी ने बयान जारी कर कहा कि यह कदम विशेष रूप से युवा भारत को लक्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कार्तिक आर्यन अपने करिश्माई व्यक्तित्व और युवाओं के साथ मजबूत जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। उनका प्रशंसक आधार, आकांक्षात्मक छवि, और विशेष रूप से मिलेनियल्स और जेनजेड के बीच उनकी पहचान उन्हें एक प्रमुख प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है। वह भारत के नए युग के यात्री की भावना को व्यक्त करते हैं, जो उन्हें थॉमस कुक के फॉरेक्स विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।

पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर, दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए है और डीजल प्रति लीटर 87.62 रुपए



नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत दे सकती है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत की बात करें तो ये 94.72 रुपए है और डीजल प्रति लीटर 87.62 रुपए है। इसके अलावा मुंबई में प्रति लीटर की कीमत 103.94 रुपए और डीजल प्रति लीटर के दाम 89.97 रुपए है। वहीं कोलकाता में प्रति लीटर पेट्रोल का भाव 103.94 रुपए और डीजल का भाव 90.76 रुपए है। आखिर में चेन्नई में प्रति लीटर पेट्रोल का दाम 100.85 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.44 रुपए प्रति लीटर है। इससे पहले 14 मार्च को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर कम हुए थे। जबकि, उससे पहले 22 मई 2022 में सरकार ने एक्साइज इयूटी कम की थी, जिसके बाद पेट्रोल 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल 16 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ था। वहीं, पेट्रोलियम मंत्री ने हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर ग्लोबल लेबल पर कच्चे तेल की कीमत अभी की तरह रही तो देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी देखने को मिल सकती है।

युनुस को...

उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। बांग्लादेश को इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक बताते हुए युनुस ने कहा था कि यह एक बड़ा अवसर हो सकता है और चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है। भारत ने इस टिप्पणी की निंदा की थी और बांग्लादेश के अधिकारियों ने युनुस के बयान पर स्पष्टीकरण जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि युनुस के बयान पर कोई सीधी टिप्पणी तो नहीं की थी लेकिन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड रवाना होने से पहले जारी किये गये अपने बयान में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार को जवाब देते हुए कहा था कि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बिम्स्टेक के केंद्र में स्थित है। उन्होंने अपने बयान में पूर्वोत्तर राज्यों की प्रधानता को रेखांकित किया था।हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनुस बिम्स्टेक समूह के नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज में भी एक साथ बैठे नजर आये। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैंतांगतार्न शिनवात्रा ने इस भोज की मेजबानी की थी। युनुस के कार्यालय ने कुछ तस्वीरें साझा कीं थीं, जिसमें चाओ फ्राया नदी के तट पर स्थित होटल शांगरी-ला में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख को मोदी के बगल में बैठे देखा जा सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके कार्यालय के एक्स हैंडलर पर मोदी की बैंकोंक में हुई सभी द्विपक्षीय मुलाकातों के फोटो अपलोड किये गये हैं मगर मोहम्मद युनुस के साथ मोदी का कोई फोटो यह रिपोर्ट तैयार करते समय तक नहीं जारी किया गया था। यानि मुलाकात तो हो गयी है मगर रिशतों की तल्बी बरकरार है और युनुस को मोदी ने अपने अंदाज में जवाब दे दिया है।वता दें कि एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद युनुस के साथ मुलाकात कर रहे थे वहीं भारत सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की घटनाओं पर कड़ा खूब भी अपनाया है। मोदी सरकार ने संसद में बताया है कि पंचांग अगस्त, 2024 से 23 मार्च तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित 2,400 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं और उम्मीद है कि पड़ोसी देश इन मामलों की गहन जांच करेगा और इनमें से किसी भी घटना को राजनीति से प्रेरित कहे बिना सभी अपराधियों को न्याय के कठरे में लाएगा। विदेश राज्य मंत्री किरणमोहन सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। दरअसल विदेश मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं के मानवाधिकार उल्लंघन का संज्ञान लिया है? इसके जवाब में मंत्री ने कहा, भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं पर ध्यान दिया है और विभिन्न अवसरों पर बांग्लादेश सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि 16 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर की बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ बैठक के दौरान ये अपेक्षाएं दोहराई गईं। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है।

नेपाल भारत के...

नेपाल भारत की 'पड़ोसी प्रथम नीति' के तहत नई दिल्ली का प्राथमिकता वाला साझेदार है।दोनों नेता भारत-नेपाल देशों और लोगों के बीच बहुआयामी साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में काम करना जारी रखने पर सहमत हुए। यह बैठक दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को जारी रखती है। पीएम मोदी ने बैठक के बाद ट्वीट किया, बैंकोंक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ एक सार्थक बैठक हुई। भारत नेपाल के साथ संबंधों को अत्यधिक प्राथमिकता देता है। हमने भारत-नेपाल मैत्री के विभिन्न चटलुओं पर चर्चा की, विशेष रूप से ऊर्जा, कनेक्टिविटी, संस्कृति और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। हमने इस वर्ष के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के कुछ प्रमुख सकारात्मक परिणामों के बारे में भी बात की, विशेष रूप से आपदा प्रबंधन और सुमोदी परिवहन के क्षेत्रों में।इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की। उन्होंने उनके सामने हिंदुओं सहित बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। दोनों नेताओं की मुलाकात बैंकोंक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई।पिछले साल अगस्त में पड़ोसी देश में शोध हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन और युनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बैठक थी।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माहील को खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आपसी हित के सभी मुद्दों को दोनों देशों के बीच रचनात्मक चर्चा के माध्यम से द्विपक्षीय रूप से संवोधित और हल किया जाना जारी रहेगा।बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत संबंधों के लिए जन-केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास करता है।

वक्फ विधेयक संसद...

इससे विशेष रूप से उन लोगों को सहायता मिलेगी जो लंबे समय से हाशिये पर रहने के साथ उन्हें आवाज और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है। श्री मोदी ने लिखा, संसदीय और समिति चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार, जिन्होंने अपने

दृष्टिकोण व्यक्त किए और इन कानूनों को मजबूत बनाने में योगदान दिया। संसदीय समिति को अपने बहुमूल्य सुझाव भेजने वाले अनगिनत लोगों का भी विशेष आभार। एक बार फिर, व्यापक बहुस और संवाद के महत्व की पुष्टि हुई है।प्रधानमंत्री ने लिखा, दशकों से वक्फ व्यवस्था पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी का पर्याय रही है। इससे विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमांदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचा है। संसद से पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे।उन्होंने कहा, अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश करेंगे जहां व्यवस्था अधिक आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगी। व्यापक रूप से, हम प्रत्येक नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह हम एक मजबूत, अधिक समावेशी और अधिक सहानुभूति रखने वाले भारत का निर्माण भी कर सकते हैं।

मणिपुर हिंसा में ...

वहां औसतन एक साल में 200 से अधिक दिन मणिपुर में बंद, ब्लैकिंड और कर्फ्यू रहता था और 1000 से अधिक लोग एनकाउंटरर्स में मारे गए थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा नहीं किया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जातीय हिंसा और नक्सलवाद में फर्क है। दो समुदायों के बीच जब नस्लीय हिंसा होती है और हथियार लेकर देश की सरकार और जनता के खिलाफ खड़े नक्सलवादियों, दोनों से निपटने का तरीका अलग-अलग है। विपक्ष को इन दोनों हिंसा में कोई फर्क नहीं दिखता है। शाह ने कहा कि यह बहुत संवेदनशील विषय है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंगाल में सैकड़ों साल तक संदेशखली में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता रहा लेकिन विपक्ष ने कुछ नहीं किया और आर जी कार मामले में भी कुछ नहीं किया। यह डबल रैटेंड ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा में 260 लोग मारे गए हैं, लेकिन बंगाल में तो चुनावी हिंसा में ही ढाई सौ लोग मार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष दो सीटें जीतकर हमें सबक सिखाना चाहता है लेकिन देश की जनता ने तीन आम चुनावों में लगातार इन्हें सबक सिखाया है। मणिपुर की जातीय हिंसा में अब तक 260 लोग मारे गए हैं जिनमें से 70 प्रतिशत पहले 15 दिन में ही मारे गए थे। शाह ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब मणिपुर में नस्लीय हिंसा हुई है। उन्होंने सदन को बताया कि मणिपुर में 1993 से 1998 तक 5 साल तक नागा-कुकी संघर्ष हुआ, जिसमें 750 मौतें हुईं और छिटपुट घटनाएं एक दशक तक चलती रहीं। उन्होंने कहा कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। 1997-98 में कुकी-पाइते संघर्ष हुआ, जिसमें 50 से अधिक गांव नष्ट हुए, 13 हजार लोग विस्थापित हुए, 352 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और 5 हजार घर जलाए गए। शाह ने कहा कि 1993 में छह माह तक मैतेई-पंगल संघर्ष में 100 से अधिक मृत्यु हुई थीं। इन हिंसाओं के दौरान भी तत्कालीन प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। उन्होंने कहा कि उस वक्त उनकी पार्टी ने हिंसा का राजनीतिकरण नहीं किया था लेकिन आज विपक्ष राजनीतिक तंत्र कसकर मणिपुर के घावों पर ममक छिड़कने का काम कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश से पहले, 7 साल के शासन में मणिपुर में एक भी दिन बंद और कर्फ्यू नहीं रहा और न ही हिंसा हुई। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के एक फैसले के कारण मणिपुर के जनजातीय और गैरजनजातीय समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि यह हिंसा न तो सरकारी विफलता है, न आतंकवाद और धार्मिक संघर्ष है, बल्कि हाई कोर्ट के एक फैसले की व्याख्या से दो समुदायों में फैली असुरक्षा की भावना के कारण हुई जातीय हिंसा है। उन्होंने कहा कि अगले ही दिन सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया था क्योंकि वहएक असंबैधानिक आदेश था।केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन किसी को बचाने या अविश्वास प्रस्ताव के कारण नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद भारत सरकार के गृह सचिव रहे अजय कुमार भट्टा को वहां का राज्यपाल बनाया गया है और अब वहां शांति है। उन्होंने सदन को बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई बैठकें हो चुकी हुई हैं, इस सदन के चलने के समय भी दो बैठकें हुई हैं और दोनों समुदायों की नई दिल्ली में बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि संभावना है। गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों समुदाय स्थिति को समझेंगे और संवाद का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि मणिपुर में स्थिति सामान्य होते ही एक भी दिन राष्ट्रपति शासन नहीं रखा जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति शासन उनकी पार्टी की नीति नहीं है।

वक्फ संशोधन ...

गुरुवार को चर्चा शुरू हुई और लगातार चली बैठक के बाद शुक्रवार तड़के यह विधेयक पारित हो गया। इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े। लोकसभा पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी थी।इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव और कानूनी विवादों को कम करना है। विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा की बैठक (शुक्रवार) रात 2:30 बजे के बाद तक चली। विपक्ष के सभी संशोधन खारिज हो गए।अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरन रिजिजू ने चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष से इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि सरकार अल्पसंख्यकों को डराने के लिए यह विधेयक लाई है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराने और गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विधेयक से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा।

वक्फ संशोधन ...

श्री रिजिजू ने कहा कि संसद का बजट सत्र, 2025, जो 31 जनवरी 2025 में शुरू हुआ था, चार अप्रैल, 2025 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच दोनों सदन गुरुवार 13 फरवरी को मध्यावकाश के लिये स्थगित कर दिए जाने के बाद सोमवार 10 मार्च को पुनः समवेत हुए थे ताकि विभाग संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुतन मांगों की जांच कर सकें और उन पर अपनी रिपोर्ट दे सकें। बजट सत्र के पहले आगके दौरान लोक सभा और राज्य सभा दोनों की कुल नौ बैठकें हुई थी। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुईं। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल 26 बैठकें हुईं।श्री रिजिजू ने कहा कि इस सत्र के दौरान, कुल 11 विधेयक (लोक सभा में 10 और राज्य सभा में 1) पुरःस्थापित किए गये। सोलह विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किए गए और 14 विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किए लौटाए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित/लौटाए गए विधेयकों की कुल संख्या 16 है। बजट सत्र, 2025 के दौरान लोक सभा की उत्पादकता लगभग 118 प्रतिशत और राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 119 प्रतिशत रही।उन्होंने कहा कि यह वर्ष का पहला सत्र होने के नाते, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार 31 जनवरी, को संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक को संबोधित किया था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी ने पेश किया था और श्री रमिश्कर प्रसाद ने इसका समर्थन किया था। इस मद्द पर लोकसभा में 12 घंटे के आबंटित समय के मुकाबले 17 घंटे 23 मिनट तक चर्चा हुई। चर्चा में 173 सदस्यों ने भाग लिया था। राज्यसभा में इसे श्रीमती किरण चौधरी ने पेश किया और श्री नीरज शेखर ने इसका समर्थन किया था। इस मद्द पर राज्यसभा में 15 घंटे के आबंटित समय के मुकाबले 21 घंटे 46 मिनट तक चर्चा की गयी। चर्चा में 73 सदस्यों ने भाग लिया था। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद उन्हें स्वीकृत किया गया।उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट शनिवार, 01 फरवरी को पेश किया गया। सत्र के पहले आग के दौरान दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा हुई। इस पर लोक सभा में 12 घंटे के आबंटित समय के मुकाबले 16 घंटे 13 मिनट तक चर्चा हुई और 169 सदस्यों ने चर्चा में आग लिया तथा राज्य सभा इस पर 15 घंटे के आबंटित समय के मुकाबले 17 घंटे 56 मिनट चर्चा हुई और चर्चा में 89 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दूसरे भाग के दौरान लोक सभा में रेल, जल शक्ति और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान किया गया। अंत में शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों को 21 मार्च को सदन में मतदान के लिए रखा गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी 21 मार्च को ही लोक सभा में पुरःस्थापित, विचार और पारित कर दिया गया।उन्होंने कहा कि केंद्र के संघर्ष में वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे और अंतिम बैच: वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों और मणिपुर राज्य के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों तथा वर्ष 2025-26 के लिए लेखानुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को भी 11 मार्च को लोक सभा में पारित किया गया। वित्त विधेयक, 2025 लोक सभा द्वारा 25 मार्च को पारित किया गया।उन्होंने कहा कि राज्यसभा में शिक्षा, रेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की गई। राज्यसभा ने केन्द्र के संबंध में वर्ष 2024-25 अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे और अंतिम बैच, वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों और मणिपुर राज्य के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों तथा वर्ष 2025-26 के लिए मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक को 18 मार्च को लौटा दिया। वर्ष 2025-20 के लिए केंद्र की अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक, 2025 को राज्य सभा द्वारा भी 27 मार्च को लौटा दिया गया। इस प्रकार संसद के सभी में संपूर्ण वितीर्थ 31 मार्च से पहले पूरा कर लिया गया।श्री रिजिजू ने कहा कि मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गयी, उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले सांविधिक संस्करण को भी दोनों सदनी में क्रमशः 3 और 4 अप्रैल, को स्वीकृत किया गया।उन्होंने कहा कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट पारित किए जाने के बाद, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित हितधारकों के सशक्तिकरण, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटारन की प्रक्रिया में दक्षता में सुधार और वक्फ संपत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। जबकि मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, इसका उद्देश्य बेहतर प्रशासन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके लागू करना है। मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को भी निरस्त कर दिया गया।संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कुशल कामकाज को मजबूत करने के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और अभिसरण लाने की मांग करता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने के लिए सशक्त बनाता है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने का प्रावधान करता है, राज्य की राधान्या और नगर निगम वाले बड़े शहरों के लिए 'शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है और राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान करता है।उन्होंने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 भी पारित किया गया जो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की

स्थापना से संबंधित है, जो सहकारिता के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण उपलब्ध कराएगा और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों संचालित करेगा। यह डिग्री कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा और ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा और सहकारिता के क्षेत्र में उक्तृछता के केंद्र विकसित करेगा।उन्होंने कहा कि भारत में प्रवेश करने और भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता के लिए कानूनी को सरल बनाने और वीजा और पंजीकरण की आवश्यकता सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025 पारित किया गया है। बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 भी पारित किया गया ताकि शासन मामकों में सुधार हो, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोटिंग में स्थिरता प्रदान की जा सके, जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और नामांकन आदि के संबंध में ग्राहकों को सुविधा प्रदान की जा सके।

खामोशी का...

उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल की निंदा की और कहा, वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रित एक गहन चर्चा भी हुई। उन्होंने कहा कि उपस्थित लोगों में आम सहमति थी कि संशोधन जम्मू कश्मीर में 'मुसलमानों और उनकी आस्था पर सीधा हमलाट है।कांग्रेस नेता व विधायक निजाम-उद-दीन भट ने कहा कि दीर्घकालिक और अन्यायकालिक मुद्दों सुर्गे पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार में सभी विधायक सदन के नेता के पीछे मजबूती से खड़े हैं।

विधेयक पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के संवेदनशील मामलों पर, इस बात पर सर्वसम्मति है कि इन मुद्दों को केंद्र के साथ बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा हाल ही में 48 जेकेएसए अधिकारियों के तबादले के राजनीतिक और प्रशासनिक निहितार्थों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। इसने जम्मू-कश्मीर सरकार और राज्यसभ के बीच एक बड़ा गतिरोध पैदा कर दिया, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा हाल ही में 48 जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएसए) अधिकारियों के तबादलों का कड़ा विरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इन तबादलों को अवैध करार देते हुए दावा किया है कि इन्हें निर्वाचित सरकार से आवश्यक मंजूरी के बिना किया गया।

सीएम...

तनवीर ने कहा कि गठबंधन जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके अधिकारों को कमतर नहीं होने देगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र के साथ उनके समन्वय को गलत नहीं समझा जाना चाहिए, उन्होंने अधिकारियों से हाल के निर्णयों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। वह प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच आया है, जिसमें गठबंधन ने उन निर्णयों के खिलाफ सख्त खूब अपनाने का संकेत दिया है, जो उनके अनुसार उनके अधिकार को दुरुक्ता करते हैं। आने वाले दिनों में आगे की कार्रवाई की उम्मीद है।

ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब एलजी ने 14 अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर और 26 सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट सहित 48 मध्यम श्रेणी के जेकेएसए अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया। एलजी ने पुनर्वामा, कुपवाड़ा, बसोहली, डोडा, अतंनगर, सुरखनी, राजौरी, नौशेरा, बारामुल्ला, श्रीनगर, गंदरबल, कटुआ, भद्रवाह और हंद्वाड़ा में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों के तबादले और नियुक्ति का आदेश दिया।अब्दुल्ला सरकार इस कदम को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का उल्लंघन मानती है, और तर्क देती है कि अखिल भारतीय सेवा केडर के बाहर के अधिकारियों का तबादला और नियुक्ति निर्वाचित सरकार का विशेष विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने औपचारिक रूप से एलजी से निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया है, उन्होंने अपने पत्र में इन बात पर जोर दिया है कि इस तरह की एकतरफा कार्रवाई सरकार के अधिकार को कमजोर करती है। इसके अलावा, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क किया है, और चिंता व्यक्त की है कि राजभवन द्वारा बार-बार हस्तक्षेप निर्वाचित नेतृत्व की वैधता को कम कर रहा है। हालांकि एलजी और सरकार के बीच तनाव कुछ समय से चल रहा है, लेकिन सिन्हा के नवीनतम निर्देश ने केंद्र शासित प्रदेश में दो सता केंद्रों के बीच दरार को और गहरा कर दिया है।

अब्दुल्ला ने मुख्य सचिव अटल डुल्लू को 48 अधिकारियों के तबादले को रोकने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि भविष्य में उनकी प्रत्यक्ष मंजूरी के बिना नए-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की कोई पोस्टिंग न हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि एलजी का हालिया कदम नौकरशाही तंत्र पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास का संकेत देता है, खासकर ऐसे समय में जब निर्वाचित सरकार अपने प्रस्तावित शासन नियमों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार कर रही है।

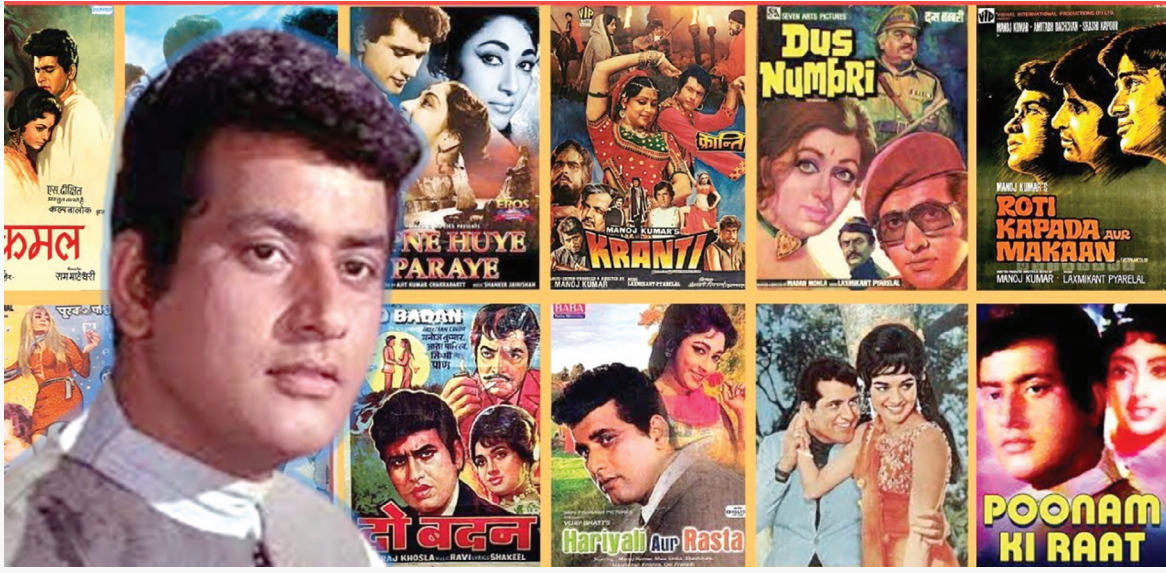
मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी आदेश ऐसे समय में आया है जब निर्वाचित सरकार लगभग एक महीने पहले बनाए गए व्यावसायिक नियमों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार कर रही थी और बिना किसी प्रम के सुचारु शासन की सुविधा के लिए मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) को भेजी थी। हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान अब्दुल्ला ने शासन में स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, जब तक हमें राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक व्यावसायिक नियम स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने पहले भी जम्मू-कश्मीर में दोहरे शासन मॉडल की आलोचना की है और इसे विनाश का नुस्खा बताया है।

कांग्रेस नेताओं ने भी सिन्हा के फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता गुलाम अरमद मीर ने तर्क दिया कि अधिकारियों के तबादलों से पहले एलजी को नए शासन नियमों की मंजूरी का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई प्रशासन में जनता के विश्वास को कम कर सकती है। मीर ने कहा, एलजी को अच्छी तरह से पता था कि दिड्डी में व्यावसायिक नियमों के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, फिर भी उन्होंने यह कदम उठाया। इससे गलत संदेश जाता है कि प्रशासन में सब कुछ ठीक नहीं है।





1960 से लेकर 1980 तक, मनोज कुमार ने हर दशक में दी यादगार फिल्में



87 साल की उम्र में पीढ़ियों को अपने अभिनय से मुतासिर करने वाला अदाकार छोड़ कर चला गया। और पीछे सौंप गया वो विरासत जिस पर उसकी फिल्मी बिरादरी को ही नहीं, पूरे भारत को गर्व है। शाहकार ऐसा जो 'पूरब' से निकल कर 'पश्चिम' के लंदन तक गुंजा। विरले ही होता है कि कोई कलाकार आए और सिल्वर स्क्रीन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन दशकों तक लगातार ऐसी फिल्में दे जो वर्षों तक दिलो-दिमाग को कुरेदती रही। हरिकृष्ण गिरि गोस्वामी ऐसी ही शख्सियत का नाम था। गोस्वामी दिलीप कुमार के जबर फैन थे। एक फिल्म देखी जिसमें दिलीप के किरदार का नाम मनोज था, फिर क्या था, अपना नाम मनोज रख लिया। देशभक्ति रंगों में समाई थी, इसलिए मां भारती को समर्पित एक से बढ़कर एक फिल्म बनाई, लोगों ने प्यार से 'भारत कुमार' पुकारना शुरू कर दिया। उन्हें अपने देश और इसकी संस्कृति पर बड़ा नाज था, और यह झलक उनकी फिल्मों में भी दिखी। फिल्मी सफर 1957 में फिल्म 'फैशन' से शुरू हुआ, जो 80 के दशक तक कायम रहा। कुछ ऐसे चलचित्र थे जिन्होंने मनोज कुमार के बहुआयामी व्यक्तित्व से सीधा साक्षात्कार कराया। 1960

मनोज कुमार के निधन पर बॉलीवुड में शोक की लहर

अभिनेता मनोज कुमार 87 वर्ष की आयु में शुक्रवार को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन से फिल्म जगत के साथ ही राजनीतिक जगत भी गमजदा है। सलमान खान, संजय दत्त और रणवीर सिंह समेत फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि जब भी भारतीय सिनेमा का जिक्र होगा वह हमेशा याद किए जाएंगे। अभिनेता सलमान खान ने एक्स हैडल पर पोस्ट शेयर कर लिखा, मनोज कुमार जी... एक सच्चे लीजेंड। आपने कभी न भूल पाने वाली फिल्मों और यादें दीं। इसके लिए धन्यवाद...। सुभाष घई ने लिखा, अलविदा मनोज जी। भारत के ग्रेट फिल्म निर्माता जिन्होंने अपनी कविता, गीत, ड्रामा, बेहतरीन शिल्पकला और सिनेमा के माध्यम से देशभक्ति से भरी फिल्मों का निर्माण किया। हमारी जेनेरेशन में हम उनके प्रशंसक हैं और उनकी देशभक्ति और सिनेमाई अभिव्यक्ति की भावना की प्रशंसा करते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक फिल्म निर्माता और व्यक्ति दोनों के रूप में उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं यह नहीं भूल सकता कि कैसे वह हमेशा मेरी फिल्मों देखने के बाद मुझे प्रेरित करते थे। न केवल मैं, बल्कि पूरा देश आपको याद करेगा। अभिनेता मनोज कुमार के निधन से आहत संजय दत्त ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर उनकी एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मनोज सर, आप हमेशा याद आएंगे। इंस्टाग्राम पर मनोज कुमार की एक तस्वीर शेयर कर रणवीर सिंह

ने भावनाएं व्यक्त कीं। वहीं, ईशा देओल ने लिखा, मनोज जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। आपकी आत्मा को शांति मिले। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं। रवि किशन ने कहा, भारत की बात सुनाता हूं... मनोज कुमार के निधन की खबर से बहुत दुख हुआ। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। भारत उनके अंदर कूट-कूट कर भरा था। उनके अंदर अद्भुत शक्ति थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके निधन से हुई क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा, मनोज जी के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पूनम दिखों ने बताया कि मनोज कुमार ने सबको सिखाया कि सार्थक फिल्मों कैसे बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा, हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि मनोज जी प्रेरणादायी और महत्वाकांक्षी दोनों थे - हर कोई उनके जैसा निर्देशक बनना चाहता है। उन्होंने न केवल सफलता हासिल की, बल्कि साफ-सुथरी और सार्थक फिल्में बनाने का उदाहरण भी पेश किया। मुझे लगता है कि जब देशभक्ति की फिल्मों की बात आती है, तो उन्होंने वाकई सबको दिखाया कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को कैसे प्रेरित किया जाए। अभिनेत्री काजोल ने 'क्रांति', 'पत्थर के सनम', 'पूरब और पश्चिम', 'रोटी कपड़ा और मकान' फिल्म का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, उनकी फिल्मों में सिर्फ फिल्मों ही नहीं थीं, वे भावनाएं थीं, वे प्रेरणा थीं। आप हमेशा याद किए जाएंगे।

से 1980 के दशक तक 7 फिल्मों में निभाए किरदार अब भी लोगों के जेहन में खुरच कर लिखे जा चुके हैं। बात उन सात फिल्मों की जो ट्रेडसेटर भी थीं, सुपरहिट भी और मर्मस्पर्शी भी। चॉकलेटी हीरो की इमेज को तोड़ती फिल्म थी शाहीद, जो 1965 में रिलीज हुई। कौन भूल सकता है भगत सिंह का वो कालजयी किरदार। ये फिल्म आजादी के बेखौफ परवानों की कहानी कहती थी। 60 के दशक में दो फिल्मों आई और दोनों ने कामयाबी की नई इबारत लिखी। एक थी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मनुहार पर बनी उपकार (1967) और दूसरी थी प्योर लव स्टोरी 'पत्थर के सनम'।

उपकार एक कल्ट फिल्म रही। गुलशन बावरा का गीत 'मेरे देश की धरती' उस दौर में भी हिट था और आज की जेन अल्फा भी इसे उतनी ही शिद्दत से जीती है, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि इस फिल्म को मनोज कुमार ने बड़े मनोयोग से रचा था। शास्त्री जी के 'जय जवान जय किसान' का नारा फिल्म का आधार था। 1967 में ही पत्थर के सनम पर्व पर आई। दो हसीनाओं के बीच जुझते एक शख्स राजेश की कहानी थी। 'राजेश' उपकार के 'भारत' से बिल्कुल अलग था। इस फिल्म को भी काफी पसंद किया गया। इसके बाद 1970 में रिलीज हुई 'पूरब और पश्चिम'। भारतीय सिने इतिहास की पहली फिल्म जिसका विषय एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस थे। एक पिता का दर्द जो कमाई के चक्कर में विदेश तो चला गया, लेकिन वहां अपनी बेटी में आए बदलाव को सहन नहीं कर पा रहा है। उस दर्द को बखूबी बयां किया गया। ये भी सुपरहिट फिल्म रही। इंदीवर का लिखा गीत 'प्रीत जहां की रीत सदा' उस दौर के हिट गीतों की लिस्ट में शुमार हुआ।

फिर आई शोर। 1972 में रिलीज फिल्म ने खामोशी से कामयाबी का शोर मचा दिया। पिता-पुत्र के रिश्ते को बुनती फिल्म ने लोगों को हंसाया तो रुलाया भी खूब। ये उस साल की सुपरहिट मूवी रही। 1974 की रोटी, कपड़ा और मकान समाज के ठेकेदारों के मुंह पर तमाचा जड़ती थी और सत्ता में बैठे रसूखदारों के कानों तक देश के युवा और मध्यम वर्ग की दुधारियां पहुंचाती थी। मल्टीस्टारर फिल्म को खूब पसंद किया गया। इसके गाने भी जोरदार थे। 1981 में आई 'क्रांति' ने एक बार फिर मनोज कुमार का दम दुनिया को दिखाया। सितारों से भरी फिल्म में देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा लोगों को खूब भाया। 'क्रांति' भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। मनोज कुमार ने 3 दशक तक फैन बेस को बनाए रखना। हर तबके तक अपनी बात पहुंचाना यही खासियत थी उनकी। मिट्टी से प्यार, संस्कृति पर गर्व और बड़ों का आदर-सम्मान करने का पाठ भी इस कलाकार ने अपनी अद्भुत शैली से सबके सिखाया। मुंह पर हाथ फेरकर, झुककर झटके से कनखियों से देखा एक स्टाइल बन गया, जिसकी नकल उतार कइयों ने कामयाबी बटोरी।

सलमान खान के द बॉलीवुड बिग वन दूर से प्रशंसक निराश

सलमान खान इन दिनों फिल्म सिकंदर को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। हालांकि, यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखाती नहीं दिख रही है। अब इस बीच सलमान ने अपने नए दूर का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम द बॉलीवुड बिग वन है। हालांकि, भाईजान के प्रशंसक उनके इस दूर से निराश हैं।



आइए आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। सिकंदर ने सलमान के फैस को काफी निराश किया है। सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों का दुख साफ झलकता है। सलमान के प्रशंसक उनसे अच्छी फिल्मों की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भाईजान के प्रशंसकों का मानना है कि उन्हें सही स्क्रिप्ट और निर्देशक चुनने की जरूरत है। एक ने लिखा, भाई ऐसे दूर में समय बर्बाद मत करो। एक लिखते हैं, ये सब छोड़ो, कोई अच्छा निर्देशक चुनें, जो आपको बेहतर तरीके से पेश करना जानता हो। एक प्रशंसक ने सलमान की सेहत की चिंता करते हुए लिखा, भाई सारी चीजों को छोड़ो और आराम करो अपनी सेहत पर ध्यान दो। कृपया थोड़ा सोच समझकर कोई स्क्रिप्ट चुनो। एक ने लिखा, ये सब छोड़ो भाई, अच्छी फिल्में निकालो। दूर में सलमान के साथ माधुरी दीक्षित, कृति सैनन, सारा अली खान, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, वरुण धवन, टाइगर श्राफ और दिशा पाटनी भी होंगे। यह दूर 4 मई को मैनचेस्टर में और 5 मई को लंदन में होगा।

निर्देशक डॉ. प्रशांत शाह का अभिनंदन



अभिनेता, निर्देशक, निर्माता डॉ. प्रशांत शाह द्वारा 200 से अधिक म्यूजिकल अल्बम रिलीज करने, युट्यूब में एक लाख से अधिक सब्सक्राइबर पूर्ण होने पर युट्यूब द्वारा सीलवर बटन प्रदान करने एवं आगामी 14 अप्रैल को उनकी फिल्म बीटू की रिलीज पर उनका लव फॉर काऊ फाउंडेशन की ओर से चेयरमेन जसमत पटेल, मेनेजींग ट्रस्टी रिद्धीश जागीरदार, टस्टी मुकेश चौहान, जैन राजनीतिक चेतना मंच के दिनेश गोसर, रायल

हेल्थ क्लब के निदेशक डॉ. डी.डी. शाह द्वारा शॉल, स्मृति चिन्ह द्वारा अभिनंदन किया गया। यह अभिनंदन कांचीगुडा स्थित रायल हेल्थ केयर सेंटर में किया गया। जसमत पटेल ने डॉ. प्रशांत को युट्यूब मे एक लाख से अधिक सदस्य पूर्ण होने पर एवं आगामी फिल्म रिलीज पर शुभकामनाएं दी और उनसे निवेदन किया है कि वे अपनी फिल्म की कमाई का कुछ अंश गोसेवा मे दान देवे।

बॉलीवुड की फिटनेस और फैशन कीन मलाइका अरोड़ा आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं हैं। एक्ट्रेस भले ही इन दिनों किसी फिल्म में नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन वो आए दिन अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अक्सर फैस का सारा अट्रेशन अपनी ओर खींच लेती हैं। अब हाल ही में

वें कि एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा भले ही 51 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी अपनी हॉटनेस से इंटरनेट का तापमान बढ़ा देती हैं। अब हाल ही में मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उनका सिजलिंग अंदाज देखकर फैस एक बार फिर से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। मलाइका अरोड़ा की लेटेस्ट तस्वीरों में आप

51 साल की मलाइका अरोड़ा ने कैमरे के सामने दिखाया हुस्न का जलवा

मलाइका अरोड़ा ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं, जिसमें वो काफी गॉर्जियस नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हमेशा अपनी हॉटनेस और बोलडनेस से फैस के बीच लाइमलाइट बटोरती रहती हैं। उनका हर एक लुक इंटरनेट पर आते ही तेजी से छाने लगता है। बता दें कि एक्ट्रेस बॉलीवुड की सबसे फिट लेडी हैं और आए दिन अपनी तस्वीरों से फैस का अट्रेशन अपनी ओर खींच लेती हैं। बता

देख सकते हैं एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर का बेहद ही स्टाइलिश आउटफिट पहना हुआ है, जिसमें वो एक से बढ़कर एक स्टाइलिंग अंदाज में पोज देती हुई नजर आ रही हैं। बालों का स्टाइलिश लुक में बन बनाकर और लाइट मेकअप कर के एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने आउटलुक को बेहद ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। उनका ये कातिल अवतार इंटरनेट पर आते ही तबाही मचाने लग गया है। बता दें कि मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग लिस्ट भी काफी जबरदस्त है।

मोनालिसा का पूल साइड लुक हुआ वायरल

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस और स्टनिंग लुक के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूल साइड की कुछ हॉट और स्टाइलिश तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में मोनालिसा ब्लू कलर की फ्रिंटेड आउटफिट में नजर आ रही हैं और उनका यह बॉल्ड अवतार फैस को खूब पसंद आ रहा है। मोनालिसा ने इन तस्वीरों के साथ एक रोमांटिक कैप्शन दिया - इश्क में, जिससे उनके फैस के बीच और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया। कमेंट सेक्शन में फैस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। किसी ने उन्हें हॉटनेस कीन कहा, तो किसी ने बॉस लेडी का टैग दे दिया। मोनालिसा की यह तस्वीरें पोस्ट होते ही वायरल हो गईं। महज कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं। फैस के अलावा कई सेलेब्स ने भी उनके लुक की तारीफ की है। इससे पहले भी मोनालिसा अपनी वेशभूषा और ट्रेडिशनल लुक वाली तस्वीरों को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं। मोनालिसा न सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री बल्कि टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। बिग बॉस में नजर आने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी।



मगही महोत्सव 2025: मगध की विरासत को समर्पित होगा यह भव्य आयोजन

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे उद्घाटन

पटना (एजेंसियां)।

मगध की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से पांच अप्रैल 2025 को बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्थित बापू टावर में 'मगही महोत्सव 2025' का आयोजन होने जा रहा है। यह एक दिवसीय भव्य कार्यक्रम सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक चलेगा और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। यह आयोजन न केवल मगही भाषा और लोक परंपरा के संरक्षण का प्रयास है, बल्कि युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी माध्यम है।

महोत्सव को मगध सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर खास तौर से आयोजित किया जा रहा है।

महोत्सव की शुरुआत सुबह 9:00 बजे प्रतिभागियों के



पंजीकरण से होगी। इसके तुरंत बाद मगध की परंपरागत गया घराने की ठुमरी गायकी से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा।

प्रख्यात गायक राजन सिजुआर की प्रस्तुति सुबह 10:15 बजे से

11:00 बजे तक होगी, जो संगीत प्रेमियों को मगध की सुरमयी संस्कृति से जोड़ देगी।

महोत्सव में पूरे दिन भर मगही भाषा, इतिहास, पुरातत्व, उद्यमिता, सिनेमा और लोक

संस्कृति पर केंद्रित सत्र आयोजित होंगे। इनमें बिहार और देश के नामी विद्वान, इतिहासकार, उद्यमी और कलाकार हिस्सा लेंगे। मगही भाषा: कल, आज और कल विषय पर सुबह 11:00 बजे से चर्चाएं होंगी, जिसमें प्रो. शिवन-रायण, डॉ. अतीश पराशर, धनंजय श्रोत्रीय और इशतेयाक अहमद अपने विचार साझा करेंगे। दोपहर 12:00 से 1:00 बजे तक मगध के इतिहास, पुरातत्व व विरासत विषय पर गहन चर्चा होगी जिसमें प्रो. आनंद वर्धन, सुजीत नयन और कुमार निर्मलेंदु वक्ता होंगे।

भोजनावकाश के बाद कार्यक्रम में मगध में उद्यमिता और मगध और सिनेमा जैसे रोचक विषयों पर संवाद होगा। यहां डॉ. सत्यजीत सिंह, अभिनेता विकास कुमार, अभिनेत्री अस्मिता शर्मा और फिल्म समीक्षक विनोद

अनुपम जैसी हस्तियां भाग लेंगी।

मगही महोत्सव में युवाओं की भागीदारी भी प्रमुख आकर्षण होगी। शाम 4:00 बजे से मगहिया युवा संवाद नामक सत्र में इंडियन आइडल फेम रीतिका राज सिंह, पवन कुमार और पूजा कुमारी जैसे उभरते हुए युवा अपनी बात रखेंगे। यह सत्र युवाओं की ऊर्जा और उनके विचारों को मगही भाषा और संस्कृति से जोड़ने की पहल का हिस्सा है।

कार्यक्रम के अंतिम चरण में मगही कवि सम्मेलन और लोकगायन का आयोजन होगा। कवि सम्मेलन में संजीव मुकेश, चंदन द्विवेदी, प्रेरणा प्रताप और अनमोल कुमारी अपनी रचनाओं से मंच को जीवंत करेंगे। समापन सत्र में मगही लोक गायिका चंदन तिवारी, रोशनी कुमारी और जितेंद्र व्यास अपनी लोकगीतों से समां बांधेंगे।

भाजपा एमएलसी ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में किया हंगामा

कुलसचिव को दी यह धमकी

पटना (एजेंसियां)।

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कुलसचिव प्रोफेसर एनके झा और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी नवल किशोर यादव के बीच विवाद बढ़ गया है। इस विवाद से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव सरेआम कुलसचिव को धमकाते दिख रहे हैं। आरोप लगा कि गुरुवार को सीनेट की बैठक के दौरान जब कुलसचिव प्रो. एनके झा अपना संबोधन दे रहे थे तब अचानक एमएलसी नवल किशोर यादव अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। उन्होंने कुलसचिव एनके झा पर अमर्यादित टिप्पणी की। इससे पहले कि प्रो. एनके झा कुछ बोलते, एमएलसी ने कहा कि 'ए बैठो तुम...तुम बैठो.. यह पटना यूनिवर्सिटी नहीं है। पालीगंज विधायक संदीप सौरभ व सीनेट के अन्य सदस्यों ने बीच-बचाव किया। इसके बाद



विधायक ने कहा कि यह कोई जंग का मैदान नहीं है। यहां सीनेट की बैठक हो रही है। समाज के प्रबुद्ध लोग यहां आए हैं। ऐसे में किसी को भी अपनी मर्यादा भूलनी नहीं चाहिए। अपनी भाषा पर हमें नियंत्रण रखना होगा। मामले में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. शरद कुमार यादव ने कहा कि एमएलसी को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। इस व्यवहार को लेकर मैंने उन्हें टोका भी। इस घटना से राज्य में गलत संदेश जाएगा।

इस मामले में कुलसचिव प्रो. एनके झा ने कहा कि बिहार के सीनेट इतिहास में यह पहली बार ऐसी दुखद घटना हुई है। जब सदस्य ने किसी कुलसचिव के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग

किया और मारने तक की धमकी दी। उन्होंने सरेआम मेरे खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। मैं इस घटना से काफी आहत हूं। भाजपा एमएलसी इससे पहले फोन पर भी मुझे धमका चुके हैं। वह नियम के विरुद्ध जाकर काम करने का दबाव बनाते हैं। राजभवन और शिक्षा विभाग को स्वतः इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए।

वहीं भाजपा एमएलसी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मैंने किसी के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। कुलसचिव को मारने की धमकी भी नहीं दी है। कुलसचिव और कुलपति के विवाद से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की मर्यादा कम हुई। मामले की जांच होनी चाहिए।

लालू की पार्टी के नेता ने सीएम नीतीश के खिलाफ लगाया पोस्टर

इफ्तार देकर ठग लिया

पटना (एजेंसियां)।

वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के नेता बिहार में सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने तो पोस्टर बार शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के सामने सीएम नीतीश कुमार का एक पोस्टर लगाया गया है। इसमें उन्हें राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के गणवेश में दिखाकर उनकी आलोचना की गई है। राजद नेता आरिफ जिलानी ने सीएम नीतीश कुमार के वक्फ संशोधन विधेयक पर उनके रुख को लेकर यह पोस्टर लगाया है।

राजद नेता ने लिखा कि गिरगिट रंग बदलता है। लेकिन यह तो उससे भी ज्यादा तेजी से रंग बदलने वाले निकले। राजद नेता ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार देकर ठगने का काम किया है। ईद में टोपी पहनकर हमलोगों को टोपी पहनाने का काम किया है। वक्फ पर धोखा दिया। एनअ-



रसी पर भी वही किया। अब जनता सबक खिखाएगी।

राजद नेता के पोस्टर लगाने से पहले दिल्ली एएस में अपना इलाज करवा रहे राजद सुप्रिंमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर वक्फ बिल के विरोध अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संघी-भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हो लेकिन हमने सदा वक्फ की जमीन बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और बनवाने

में मदद की है। मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में नहीं हूँ अन्यथा अकेला ही काफी था।

उन्होंने कहा कि मैं सदन में नहीं हूँ तब भी आप लोगों के ख्यालों, ख्वाबों, विचारों और चिंताओं में हूँ यह देख कर अच्छा लगा। अपनी विचारधारा, नीति और सिद्धांतों पर प्रतिबद्धता, अडिगता और स्थिरता ही मेरे जीवन की जमा पूंजी है।

मुस्लिम नेताओं-कार्यकर्ताओं का जदयू छोड़ना जारी



पटना (एजेंसियां)।

वक्फ संशोधन विधेयक पर बिहार में सियासी घमासान जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी झटका लगा है। जनता दल यूनाइटेड का रुख विधेयक में पक्ष में होने के कारण पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज हो गए हैं। एक-एक कर अब तक चार नेत-13ओं ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। इनमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मो. शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मो. तबरेज सिद्दीकी अलीगं, भोजपुर से पार्टी सदस्य मो. दिलशान राईन और जदयू के पूर्वी चंपारण जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रवक्ता कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जदयू के रुख को लेकर नाराजगी जताई है। कहा कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ दिया है।

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव शाहनवाज मलिक ने अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी में सीएम नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए लिखा कि हम जैसे लाखों करोड़ों मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप सेक्युलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं। लेकिन, अब यकीन टूट गया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर जदयू के पक्ष से हमलोगों को गहरा आघात लगा है। हमलोग लोकसभा में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरीय नेता ललन सिंह के तेवर से आहत हैं। उन्होंने जिस तरह का वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे पार्टी को वोट करने वाले मुसलमान मर्माहत हैं। यह बिल मुसलमानों के विरुद्ध है। हम किसी सूत्र में इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह बिल संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि हमलोग अपनी जिंदगी के कई वर्ष इस पार्टी को दे दिया। इसलिए मैं स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा हूँ।

जहानाबाद शहर में ट्रैफिक की होगी डिजिटल निगरानी

ई-चालान और कैमरों से बढ़ेगी सुरक्षा

पटना (एजेंसियां)।

आने वाले दिनों में जहानाबाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बदलने वाली है। अब शहर के प्रमुख चौकों पर पटना की तर्ज पर रेड, येलो और ग्रीन ट्रैफिक लाइट लगाई जाएंगी। रेड लाइट का मतलब होगा रुकना, ग्रीन लाइट आगे बढ़ने की अनुमति देगी, और येलो लाइट ड्राइवर्स को चेतावनी देगी कि वे धीमे हो जाएं क्योंकि रेड लाइट आने वाली है।

ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए शहर के प्रमुख चौकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से वाहनों के नंबर प्लेट की तस्वीर ली जाएगी और जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा, उसे ऑटोमेटिक तरीके से ई-चालान जारी किया जाएगा। यह सिस्टम खासतौर पर ओवरस्पीडिंग और रेड लाइट जंप करने जैसी गलतियों पर नजर रखेगा।

इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्रमुख स्थानों की पहचान कर ली है। काको मोड़, अरवल मोड़ और अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का प्रस्ताव पहले ही दिया



जा चुका है।

फिलहाल, सड़कों के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसके पूरा होते ही इन स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरों की स्थापना का काम शुरू कर दिया जाएगा। खासकर काको मोड़ और अरवल मोड़ के पास कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को ट्रैक किया जा सके।

अभी तक ट्रैफिक पुलिस इन

चौराहों पर मैनुअली ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, जिससे कई वाहन चालक चालान से बच निकलते हैं। लेकिन ई-चालान सिस्टम लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। इससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। खासकर, बाइक सवारों के लिए हेलमेट न पहनने जैसी लापरवाहियों पर भी निगरानी रखी जाएगी। ट्रैफिक डीएसपी नवीन

कुमार ने बताया कि इस प्रस्ताव को जनवरी में पेश किया गया था, लेकिन सड़कों के चौड़ीकरण के कारण इसका कार्यान्वयन रुका हुआ है। वहीं, जिला परिवहन पदाधिकारी राहुल कुमार ने भी आश्वासन दिया है कि ई-चालान सिस्टम जल्द शुरू किया जाएगा। यह नया कदम जहानाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और अनुशासित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

पुलिस की बेरहम पिटाई से एक युवक का पैर टूटा, दूसरे की हालत नाजुक

बेगूसराय (एजेंसियां)।

बेगूसराय जिले में पुलिस की कथित बेरहमी का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। जहां हेलमेट न पहनने पर तीन युवकों को पुलिस ने इस कदर पीटा कि एक का पैर टूट गया और दूसरे की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घायल युवक आदित्य राज दिल्ली में रहकर यूप-ीएससी की तैयारी कर रहा है। उसने पुलिस पर मारपीट के साथ-साथ जातिस्वचक गालियां देने और एक हजार रुपये वसूली का आरोप भी लगाया है।

यह घटना 30 मार्च की रात की बताई जा रही है, जब नगर थाना की गश्ती टीम ने रात में बाइक से जा रहे तीन युवकों को पावर हाउस रोड के पास रोक लिया। हेलमेट न होने और कागजात की पुछताछ के दौरान मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिसकर्मियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी।

घायल आदित्य राज ने बताया कि वह अपने ननिहाल गाछी टोला आया हुआ था और बीए थर्ड ईयर की परीक्षा देने के लिए रुका था। उसी दौरान दिल्ली से

उसका दोस्त इम्तियाज मिलने आया और वहीं रुक गया। रात करीब 12:30 बजे उसे यह सूचना मिली कि उसके मौसेरे भाई सन्नी कुंज प्रभाकर के दादा का निधन हो गया है। इसी खबर के बाद वे तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर नींगा गांव की ओर रवाना हुए।

हड़बड़ी में हेलमेट न पहनने के कारण उन्हें पावर हाउस रोड के पास पुलिस ने रोक लिया। आदित्य ने बताया कि जैसे ही उन्होंने दादा की मृत्यु की बात बताई, पुलिसकर्मी भड़क गए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।

आदित्य राज ने दावा किया कि पुलिस ने उसके सिर पर जोरदार डंडा मारा, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। वहीं, सन्नी को इतनी जोर से डंडा मारा गया कि उसका पैर टूट गया और वह बेहोश हो गया। तीसरे युवक इम्तियाज को भी पीटा गया, लेकिन उसकी चोटों अपेक्षाकृत कम थीं। आदित्य ने कहा कि मारपीट के बाद उन्हें बोलेरो में पीछे की सीट पर बैठाया गया और फिर गाछी टोला, सुभाष चौक और पावर हाउस रोड के रास्ते घुमाया गया।